● वर्ष-3
● अंक-302
रायपुर, बुधवार
31 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› बरसात में बनाए घर को खूबसूरत...

यूपीए ने किसानों को लाभ नहीं दिया था- कृषि मंत्री

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साल 2006 में में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया जाए, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक पूरक प्रश्न पूछा और कहा कि आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों की जान चली गई। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को नौकरी देने पर विचार कर रही है।

इस सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं था, जो किसानों के सामने आने वाले मुद्दों पर था। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है।

यूपीए ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने से किया था इनकार

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था, जिसमें किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा, कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी और उसमें कहा गया था कि फसलों के लिए एमएसपी की गणना में लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़ा जाना चाहिए। उनकी सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। मेरे पास दस्तावेज हैं। उनके मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा था कि 50 प्रतिशत लाभ नहीं दिया जा सकता। उस समय शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि यह नहीं दिया जा सकता।

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने कई फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने दावा किया, मोदी सरकार ने एमएसपी में 50 प्रतिशत लाभ जोड़ा है।

संसद में भयंकर भिड़ गए अनुराग-राहुल!

लोकसभा में उस समय हंगामा हुआ जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर परोक्ष कटाक्ष किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा के अंदर उनका अपमान करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। ठाकुर के इस तंज पर कि जिनकी जाति का पता नहीं है, वे जाति जनगणना के बारे में बात करते हैं, गांधी ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने कहा था कि जो जाति के बारे में नहीं जानता, वह जनगणना की बात करता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है। मैं इन गालियों को खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है और मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता। मैं इन गालियों को खुशी से स्वीकार करूंगा...अनुराग ठाकुर ने मुझे गालियां दी हैं और मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता। राहुल गांधी ने ठाकुर के भाषण को बीच में रोकते हुए कहा कि आप जितना चाहें मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित कराएंगे। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने सदन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। हालाँकि, सांसद अपना असंतोष व्यक्त करते रहे। शोर-शराबे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो भी दलितों के लिए बोलता है, उनके लिए लड़ता है, उन्हें दूसरों से गालियां खानी पड़ती हैं. मैं सारी गालियां खुशी-खुशी खा लूंगा...महाभारत में अर्जुन की तरह, मैं सिर्फ देख सकता हूं मछली की आँख, हम जातीय जनगणना करा देंगे, आप मुझे जितनी बार चाहें गाली दे सकते हैं।

भूस्खलनः अब तक 106 लोगों की गई जान

रेस्क्यू में लगी सेना और एनडीआरएफ

वायनाड (केरल)। वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के जवाब में, केरल सरकार ने 30 और 31 जुलाई को दो दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस घटना मेम कम से कम 106 लोग मारे गये हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सोमवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 93 शव बरामद किए गए हैं और 128 लोग घायल हुए हैं। वायनाड के पहाड़ी जिले में लगातार मानसूनी बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक हो गई है और कई लोगों के कीचड़ और मलबे में फंसे होने की आशंका है क्योंकि बचाव अभियान जारी है। वायनाड में भूस्खलन आपदा के जवाब में, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) जिला मुख्यालय (केरल और माहे) और आईसीजी स्टेशन बेपोर ने आपदा राहत टीमों (डीआरटी) को प्रभावित क्षेत्र में भेज दिया है। आपदा से प्रभावित समुदायों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए टीमें सक्रिय हैं। राहत टीम में उच्च प्रशिक्षित आईसीजी कर्मी और एक समर्पित चिकित्सा टीम शामिल है। टीम आवश्यक आपदा राहत सामग्री से सुसज्जित है, जैसे बचाव कार्यों के लिए रबर की फुलाने योग्य नावें, पानी और जल निकासी के मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए डीजल चालित पंप सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कर्मियों की सुरक्षा के लिए रेनकोट और गम बूट। भारतीय सेना एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही है। मुदक्कयी गांव से लगभग 150 लोगों को बचाया गया है, चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऑपरेशन के लिए पहले से ही तैनात लगभग 225 कर्मियों की कुल क्षमता वाली चार टुकड़ियों के अलावा, लगभग 140 कर्मियों की क्षमता वाली दो और टुकड़ियां तिरुवनंतपुरम में स्टैंडबाय पर हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अल्प सूचना पर एयरलिफ्ट किया जा सके।

दिल दहला देने वाली आपदा, पूरा इलाका नष्ट हो गया

आज सुबह हुए वायनाड भूस्खलन में मृतकों के शवों को नीलांबुर तालुक अस्पताल लाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वायनाड में हुआ भूस्खलन एक दिल दहला देने वाली आपदा है। वहां बहुत भारी बारिश हुई। पूरा इलाका नष्ट हो गया है। भूस्खलन की घटना के बाद यहां के एक स्वास्थ्य केंद्र में शवों की कतार के बीच लोग अपने प्रियजनों को ढूंढते नजर आए। परिजनों के शव देखकर जहां कुछ लोग फूट-फूटकर रोने लगे, वहीं किसी अपने का शव इनमें ना पाकर उनके सकुशल होने की आस में कुछ ने राहत की सांस ली। वायनाड जिले के मेप्पाडी गांव के एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।

राष्ट्रहित का राजनीतिकरण न करें, बजट में सभी का रखा गया ध्यानः नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में एक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की प्रभावशीलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब भारत में ग्रामीण सड़क विकास के लिए एक व्यापक और अचूक योजना शुरू की गई थी। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि 60 साल पहले, जब नेहरू लगातार 3 बार चुनाव जीते, तो देश में आजादी का उत्साह था और उनका मुकाबला बेहद कमजोर और बिखरे हुए विपक्ष से था। हालाँकि, 2024 में, मोदी जी ने एक मजबूत विपक्ष के खिलाफ अपना तीसरा कार्यकाल जीता। यह जनादेश स्थिरता, निरंतरता, सुशासन और विकसित भारत के विकास के लिए है। नड्डा ने आगे कहा कि इस बार का बजट सर्वसमावेशी है। ये सतत विकास और आर्थिक लचीलापन का बजट है। आज दुनिया के विकसित देशों की आर्थिक स्थितियां डगमगा रही हैं, लेकिन हम economic resilience के साथ कोविड महामारी के बाद मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बजट के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी नवाचार, सामाजिक कल्याण और सभी के लिए समान अवसर हैं। यह दूरदर्शी बजट है जो विकास को गति देने वाली नीतियों को गति देगा। यह बजट सभी का ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापक और आर्थिक सामाजिक विकास को समर्पित है। इस बजट की प्राथमिकता है- बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी नवाचार, समाज कल्याण। ये बजट पासपोर्ट समान अवसर पद वाला है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसके बाद आप बजट की कितनी ही बातें कर लो, वो देश के लिए कितने हित का था, वो समझ आ जाता है। आंकड़ों से देश नहीं चलता है, लीक प्रूफ व्यवस्था के साथ last mile delivery assurance जरूरी है। इसलिए मोदी जी ने डीबीटी को डिजिटल इंडिया बनाया और डीबीटी के माध्यम से 37 लाख करोड़ रुपये देश के आम नागरिकों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए।

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए की सिफारिश

नई दिल्ली/बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के लिए दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। जिसमें कॉलेजियम ने अधिवक्ता बिभू दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद (ए.के. प्रसाद) का नाम शामिल किया है। इस सिफारिश की प्रक्रिया की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ ने की, और इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी. आर. गवई भी शामिल थे। इसे पहले बीते 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद इन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम से की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मामलों से अवगत सुप्रीम कोर्ट के एक जज के विचार मांगे गए थे, लेकिन एकमात्र सलाहकार जज ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिफारिश की गई सूची में एक नाम उनके रिश्तेदार का था।

पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे बंगाल विधानसभा अध्यक्ष

कोलकाता । पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सदन के अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय पर कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। भाजपा नेता ने प्रधान सचिव को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के इशारे पर विपक्षी दल द्वारा पेश किए गए सभी स्थगन प्रस्तावों को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा रखे गए प्रस्तावों का उद्देश्य लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। अधिकारी ने कहा कि बंद्योपाध्याय अध्यक्ष की भूमिका की आलोचना होने पर विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बंद्योपाध्याय सरकार की अक्षमता को छिपाने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारी ने विपक्ष के सदस्यों के भाषणों के अंशों को बिना किसी वैध कारण के हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं .

लगातार हो रहे आतंकी हमले बड़ा रूप ले सकती हैं : अब्दुल्ला

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले देश के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि ऐसी घटनाएं बड़े संघर्ष का कारण बन सकती हैं। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, ''हम चाहते हैं कि दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के बीच शांति बनी रहे, लेकिन इसके उलट टकराव का माहौल बनाया जा रहा है। हमें डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और लोग चाहेंगे कि सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है क्योंकि उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर आतंकवादी सीमा पार से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है... अल्लाह हमें इससे बचाए। हम प्रार्थना करेंगे कि वे (पाकिस्तानी) भी समझदार बनें। मुद्दे इस तरह से हल नहीं हो सकते, वे केवल जटिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वे शांति की दिशा में काम करें और हम वह दिन देखें।'' पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में हमले करने के लिए उच्च प्रशिक्षित कमांडो भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक हुए हमलों के तरीके से संकेत मिलता है कि हमलावर सैनिकों के विशिष्ट समूह के सदस्य हो सकते हैं।

हिमाचल के विद्यालयों में सुबह की सभा में होगा राष्ट्रगान

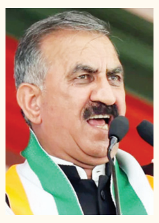

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा में नियमित रूप से राष्ट्रगान का आयोजन करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जारी एक बयान में कहा कि इन गतिविधियों से युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होगी तथा एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। जिससे वे राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत शारीरिक शिक्षा और योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी स्कूलों में विद्यार्थी प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट शारीरिक व्यायाम के लिए समर्पित करें।

इंडिया ब्लॉक की रैलीः उजागर हुआ कांग्रेस का दोहरा चेहरा

नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोग इंडी गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते देखकर हैरान हैं, जिन्हें कोर्ट ने जेल में रखा है। यह समझना कठिन है कि इंडी गठबंधन ने किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मामले जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल में रखना या जमानत देना न्यायपालिका का निर्णय है। संजय सिंह को कोर्ट द्वारा जेल भेजा गया और रिहा किया गया, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसी तरह केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जांच एजेंसियां या सरकार केवल कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत और बहस करती हैं लेकिन कोर्ट के जमानत देने के निर्णय का अनादर करने की कोशिश नहीं करती। जांच एजेंसियां हमेशा परिपक्वता के साथ पेश आई हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का बहाना बना कर जमानत पाने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा के बिखरे वोट बैंक को सहेजने में जुटे सीएम योगी

अमित शर्मा

केंद्र की घुट्टी पीकर लखनऊ पहुंचे भाजपा नेताओं के सुर अचानक एक हो गए हैं। अब हर मंच से सबके एक साथ होने के न केवल संदेश दिए जा रहे हैं, बल्कि एक सुर में बोलकर यह संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि हम सब साथ-साथ हैं। अब तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तनातनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से दोनों उपमुख्यमंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं के गायब रहने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक से वापस जाने के बाद यूपी भाजपा के नेताओं के सुर पूरी तरह बदल गए हैं।

भाजपा के अंदरखाने चर्चा है कि आपसी मतभेद से नुकसान की आशंका से केंद्र ने सबको कदमताल करते हुए एक साथ चलने की चेतावनी दी है। सरकार और संगठन को पूरी तरह एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया गया है। %महत्त्वाकांक्षा% पाल रहे नेताओं को भी पार्टी के हित में काम करने के लिए %मिलजुलकर% रहने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि अब वे न केवल एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हर विपक्षी चाल को भोथरा करने का दम भी भर रहे हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ली गई एक बैठक प्रदेश में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया और बैठक के बाद एक साथ फोटो खिंचवाकर एक साथ होने का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे से झलकती खुशी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव में भाजपा के बिखरे वोट बैंक को सहेजने में जुट गए हैं।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ओबीसी समुदाय को समाज का %हनुमान% करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी हिंदू समाज की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये हनुमान परास्त कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू समाज में फूट डालने का षड्यंत्र रचा था, आज विपक्षी दल वही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज में बजरंगबली की शक्ति है, बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका के दहन में देरी नहीं लगेगी।

योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह संकेतों में ओबीसी समाज को हनुमान की संज्ञा दी है, माना जा रहा है कि वे इसी वर्ग को साधते हुए भाजपा की राजनीति को आगे बढाने की कोशिश करेंगे। यानी भाजपा पूरी मजबूती के साथ गैर-यादव ओबीसी को पूरे दमखम के साथ साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह अपने कार्यकाल में ओबीसी समाज को दी गई नौकरियों की जानकारी दी है, उसे इस वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है।

60 प्रतिशत नौकरी ओबीसी को

दरअसल, पिछड़ा वर्ग समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार में साढ़े छह लाख सरकारी भर्तियों में से 60 फीसदी लोग ओबीसी समाज के भर्ती हुए हैं। यह दावा इस अर्थ में बेहद महत्वपूर्ण है कि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के दौरान इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। खुद सरकार के ही एक महत्वपूर्ण नेता ने दूसरे विभागों की भर्तियों की जानकारी मांगकर सरकार को असहज कर दिया था। हालांकि, मुख्यमंत्री के इस जवाब ने पक्ष-विपक्ष के लोगों को जवाब देने के साथ ही जनता के वर्ग को भी संतुष्ट करने का काम किया है, ऐसा माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री जानते हैं कि समाजवादी पार्टी तेजी से अपने आपको मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा उन्होंने सपा पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा की आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम केवल एक ही जाति के भर्ती किये गए थे। यानी भाजपा एक बार फिर गैर-यादव ओबीसी समुदाय को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समाज के लोगों का रोजगार छीना था, जबकि भाजपा ने इस समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है।

बारिश में लबालब गंगरेल डैम, कभी भी खोला जा सकता है गेट

धमतरी। 10 दिनों की बारिश से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा गंगरेल बांध का जलस्तर सुधर गया है। लगातार कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बनी हुई है। गंगरेल बांध अब 80 फीसदी भर चुका है। जिससे गंगरेल डेम का गेट कभी भी खोला जा सकता है। 32 टीएमसी वाले बांध में 27 टीएमसी से ज्यादा पानी भर गया है। प्रति सेकंड 35 हजार क्यूसेक से ज्यादा का पानी आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुनादी और बाढ़ से निबटने तैयारी में प्रशासन जुटी हुई है।

22 जुलाई तक सूखे की मार झेल रहा छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा धमतरी का गंगरेल बांध अब अपनी क्षमता से 80 फीसदी भर गया है। गंगरेल बांध खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे है। कैचमेंट एरिया कांकेर, चारामा से पानी की आवक के अनुसार गंगरेल बांध के गेट को कभी भी खोलकर महानदी में पानी बहाया जा सकता है। खतरे को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग द्वारा महानदी किनारे बसे गांव को अलर्ट किया है। इधर रुद्री बैराज को पहले ही खाली किया जा रहा है। रुद्री बैराज के गेट नंबर 5 और 6 को खोलकर महानदी में 3 हजार क्यूसेक पानी बहाया जा रहा है।

गंगरेल समेत माडमसिल्ली, सोंढूर और दुधावा बांध अब जल्द ही लबालब भरने वाला हैं। बांध के

कैचमेंट एरिया में रुक-रुककर बारिश हो रही है। जिसका पानी बांधों में पहुंच रहा है। बांध के कंट्रोल रूम के मुताबिक गंगरेल बांध में सोमवार शाम 6 बजे फिर आक्क बढ़ी। बांध में 16400 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। जिससे जलस्तर 346.80 मीटर पर पहुंच गया। 26.123 टीएमसी भर चुका था। गंगरेल बांध का जलस्तर क्षमता 348 ।70 मीटर है, जिसके मुताबिक भरने में अब महज 2 मीटर यानि 6 टीएमसी पानी की और जरूरत है। बांध में आवक और बरसात के बचे 2 महीने को ध्यान में रखकर इसी हफ्ते गंगरेल बांध का गेट खुलने की उम्मीद है। अभी पेन स्टाक गेट से 1100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

इस मामले पर अपर कलेक्टर जीआर मरकाम ने बताया कि लगातार गंगरेल बांध की स्थिति में सुधार हुई है। बांध भरने वाला है। गंगरेल बांध के गेट खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। कभी भी गेट खोला जा सकता है।

जान जोखिम में डाल कर रहे आवाजाही, दो साल में पूरा नहीं हुआ पुल का काम

गरियाबंद। जिले के अमलीपदर सूखा तेल नदी पर 40 गांव के लोगों की सहूलियत के लिए 2022 में 7 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पुल निर्माण की शुरुवात की गई थी। पीडीडब्ल्यूडी के सेतु शाखा के देखरेख में काम शुरू तो हुआ पर दो साल में भी काम पूरा नहीं हो पाया। पांच में से एक भी पिल्हर खड़ा नहीं किया गया है। अब बारिश के दिनों में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने जा रहे। वहीं आवाजाही करने वाले हर एक सख्स को खतरा मोल लेना पड़ रहा है।

अमलीपदर को नेशनल हाइवे 130 से जोड़ने वाले इस रपटे पर अब आवाजाही करना किसी दुर्घटना को न्यौता देने के बराबर है। पार जाना मजबूरी है। ऐसे में हर जरूरतमंद इस जानलेवा रास्ता को आवाजाही के लिए मजबूरी में चयन करता है। शिक्षकों को स्कूल जाना हो या हायर सेकेंडरी के बच्चों को स्कूल आना हो, वे जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। आए दिन हादसे भी हो रहे, कुछ लोगों की जान भी गई, पर मजबूरी के चलते इस पर गुजरना लोगों ने नहीं छोड़ा है।

रपटा पार करते हुए छात्राएं गिरी तो उन्हें भीगे कपड़े में ही दिनभर स्कूल में गुजारना पड़ जाता है। पुल के अभाव में इलाके का कारोबार ठप सा हो गया है। लगातार मिल रहे आश्वासन के बाद भी सुविधा के लिए तरस रहे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया है। अनदेखी और लापरवाही की हदे पार कर चुकी विभाग इस मामले में कुछ भी कहने से मनाही कर दिया।

विस्फोटक सामाग्री के साथ 2 नक्सली मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार

सुकमा। थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत कैम्प बेदरे से तोमेश वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जगरगुण्डा के हमराह जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाईटर का बल एवं सुरेन्द्रन, सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 165 वाहिनी सीआरपीएफ का बल की संयुक्त पार्टी नक्सल गस्त सर्चिंग हेतु ग्राम दुरनदरभा, चिमलीपेंटा व आस-पास क्षेत्र जंगल की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान ग्राम दुरनदरभा के जंगल के पास से घेराबंदी कर 02 संदिग्धों को पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्धों से पूछताछ करने पर अपना नाम ओयम छोटू पिता केशा (मिलिशिया सदस्य, दुरनदरभा) निवासी ग्राम पटेलपारा दुरनदरभा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, एवं कोरसा हुंगा पिता कोरसा मंगडू (मिलिशिया सदस्य, दुरनदरभा) निवासी ग्राम पटेलपारा दुरनदरभा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा का होना तथा नक्सल संगठन में उपरोक्त पदों पर कार्य करना बताया गया। गिरफ्तार नक्सली ओयम छोटू पिता केशा के कब्जे से 4 नग डेटोनेटर, 2 नग जिलेटिन रॉड, 3 मीटर बिजली वायर 2 नग पेंसिल सेल, नक्सल साहित्य एवं कोरसा हुंगा पिता मंगडू के कब्जे से बारूद लगभग 100 ग्राम, टॉप टाईगर बम 2 नग, टिकली फटाका 3 नग, 2 नग माचिस, नक्सल साहित्य बरामद किया गया। उपरोक्त सामाग्री को रखे जाने के संबंध में गहन पूछताछ करने पर बताये कि बड़े नक्सलियों के आदेश पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रखना तथा मौके पाकर सुरक्षा बलों के आने-जाने वाले मार्ग में आईईडी लगाने के लिये आना बताये। उक्त कृत्य विधि विरूद्ध पाये जाने से दोनों नक्सली व अन्य नक्सलियों के खिलाफ थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 15/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों नक्सलियों के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

पहली ही बारिश में दो टुकड़ों में बंटी सड़क

ठेकेदार और इंजीनियर ने मिलकर उन सड़कों में किया गुणवत्ताहीन कार्य

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहली ही बारिश ने सड़क गुणवत्ता की पोल खोल दी। दरअसल जिस क्षेत्र के सड़कों के निर्माण में जवानों ने अपनी शहादत दी उस इलाके की सड़कों में ठेकेदार और इंजीनियर ने मिलकर गुणवत्ताहीन कार्य किए हैं। इसी का नतीजा है कि पहली ही बारिश में डेढ़ किमी की डामर सड़क दो टुकड़ों में बट गई है।

सरकार अंदुरुनी क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण कर गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने का हर संभव मदद व प्रयास कर रही है। इसमें छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार काफी हद तक सफल भी हो रही है। अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिन-रात सुरक्षा बलों द्वारा पहरी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा रही है। अंदरूनी इलाकों में सड़कों को बनाने में कई जवानों की शहादत भी हुई है। इससे सरकार और प्रशासन में बैठे लोग भी वाकिफ हैं। ठेकेदार और इंजीनियर ने मिलकर इन सड़कों में गुणवत्ताहीन कार्य किए हैं। इसके चलते पहली ही बारिश में सड़क दो टुकड़ों में बट गई है।

1.53 किमी में 49.99 लाख रुपयों की लागत में सड़क बनाई गई है, लेकिन इन सड़कों का हाल देकर ऐसा लगता है कि ठेकेदार और इंजीनियर ने इन्हें बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंजीनियर अगर इस सड़क पर 55 मिनट समय भी उस जगह पर जाकर दिया होता तो शायद इस सड़क बनवाने में शहीद जवानों की आत्मा को शांति मिलती, लेकिन ठेकेदार के साथ मिलकर इंजीनियर ने अपनी कमीशन के चलते घर बैठे इस डेढ़ किलोमीटर की सड़क का मूल्यांकन कर पूरी राशि आहरण करने ठेकेदार का मदद किया है। इस डेढ़ किलोमीटर की सड़क में ठेकेदार व इंजीनियर मिलकर गुणवत्ताहीन कार्य करा कर इस सड़क पर एक भ्रष्टाचार की लकीर लिख गए। इसी का नतीजा है कि पहली ही बारिश में सड़क दो टुकड़ों में बट गई है।

अवैध गांजा-दारु बिक्री का किया विरोध, तो मार दिया कटर

दुर्ग। जामुल नगर पालिका में इन दिनों बदमाश बेखौफ हैं। ताजा मामला पार्षद के पिता पर जानलेवा हमले का है। पार्षद की माने तो जामुल नगर पालिका से कुछ दूर पर नहर किनारे खुलेआम सट्टा खिलाने के साथ ही अवैध शराब और गांजा बिक रहा है। पार्षद ने इसका विरोध किया और कई जगहों पर जाकर शिकायत की।बस फिर क्या था अवैध काम में लगे लोगों की आंखों में पार्षद कील की तरह चुभने लगे।इसलिए पूर्व पार्षद को चेतावनी देने के लिए बदमाशों ने बुजुर्ग माता पिता को निशाना बना डाला।

जामुल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद नरेंद्र देवदास ने बताया कि उसके वार्ड में घर से 100 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे अवैध शराब बेची जाती है। गांजा बेचा जाता है।सट्टा खिलवाया जाता है। जिसका विरोध किया गया। इसकी शिकायत नगर पालिका और पुलिस दोनों जगह पर की गई। इसके बाद से इस अवैध काम को करने वाला कृष्णा साहू उससे दुश्मनी रखने लगा था।

पार्षद नरेंद्र देवदास के पिता सत्यम ट्रेलर सुपेला में काम करते हैं। सोमवार देर रात जब वो काम से वापस आ रहे थे।उसी दौरान कुछ लोग नशे की हालत में गाली गलौज करने लगे।जब पार्षद के पिता ने उन्हें रोका तो उल्टा पिता से ही उलझ गए।इस दौरान पार्षद की मां भी मौके पर पहुंची।लेकिन बदमाशों ने अपने पास रखे कटर से पिता के सिर पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के सिर पर कटर लगने से वो लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही पार्षद नरेंद्र वहां पहुंचा और पिता को लेकर जामुल थाने पहुंचा। जामुल पुलिस बुजुर्ग को लेकर सुपेला अस्पताल पहुंची और उसका मुलाहिजा किया गया। पुलिस को पार्षद ने वो कटर भी दिया है, जिससे उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। नरेंद्र के पिता सुरेंद्र देवदास ने बताया कि वो सुपेला घड़ी चौक स्थित सत्यम टेलर्स में काम करता है। रोज की तरह शाम को अपने घर जाता है।वो शाम को अपने घर जा रहा था।उन्हें मारने के लिए पहले ही कुछ लड़के बैठे थे।उन्हें देखते ही लड़कों ने लड़ाई झगड़ा शुरु कर दिया।

छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी की कार से शराब तस्करी

- **दो आरोपी गिरफ्तार, 10 पेटी शराब जब्त, कार्रवाई की भनक लगते ही आरक्षक फरार**

बिलासपुर। सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक अपनी लक्जरी कार से देसी शराब की तस्करी करा रहा था। इसकी सूचना पर मोपका पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कार से 10 पेटी देसी शराब, खाकी वर्दी, एक प्लास्टिक केन, लाठी, खाकी रंग का बॉडीगार्ड कपड़ा, आरक्षक के नाम की बैंक पासबुक, उसका आईडी कार्ड जब्त किया गया है। वहीं इसकी भनक लगते ही मामले में शामिल आरक्षक नीलकमल राजपूत पेट्रोलिंग वाहन को छोड़कर भाग निकला है। सरकंडा पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

मोपका पुलिस के मुताबिक, सोमवार की देर रात देसी शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने मोपका चौक पर घेराबंदी की। मुखबिर के बताए अनुसार चिल्हाटी मोड़ की ओर से आ रही रेनाल्ट कार को पुलिस ने रोका और कार सवार बलराम यादव निवासी कंसा चौक टिकरापारा और नवीन बोले उर्फ भज्जी निवासी दयालबंद गुरुनानक स्कूल के सामने को पकड़ा। पूछताछ में दोनों गोलमोल जवाब देने लगे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें पांच बोरियों में 480 पाव देसी शराब का जखीरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर युवकों को थाने ले आई। थाने में कड़ाई से पूछताछ में नवीन ने बताया कि वह सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक नीलकमल राजपूत के कहने पर शराब लेकर आ रहा था।

चौकी प्रभारी ने तत्काल मामले की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। इधर शराब पकड़े जाने की भनक आरक्षक को भी लग गई। इस दौरान वह सकरी थाने में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद

था। मामले में जुर्म दर्ज होने की जानकारी लगते ही वह पेट्रोलिंग वाहन छोड़कर फरार हो गया। इधर पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। पुलिस की टीम ने फरार आरक्षक के मुंगेली स्थित घर पर रेड कार्यवाही की है, जहां वह नहीं मिला है। पुलिस की टीम ने पकड़े गए ड्राइवर और शराब तस्करी से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

आरोपी नवीन ने बताया कि वह भज्जी चखना दुकान में काम करता है। काम के दौरान ही वह दिनभर में धीरे-धीरे शराब खरीदकर इकठ्ठा करता है। इसके बाद वह रात को शराब खपा देता था। आरक्षक नीलकमल ने उसे 45 हजार रुपये देकर शराब लाने के लिए कहा था। उन्ही रुपयों से उसने अलग-अलग दुकानों से शराब खरीदी की। इसके बाद वह इकठ्ठी शराब को लेकर आरक्षक को देने के लिए जा रहा था। शराब जब्त करने के बाद पुलिस ने कार की बारीकी से तलाशी ली। इस दौरान कार में पुलिस की वर्दी, एक प्लास्टिक का केन, एक प्लेट जिसमें पुलिस लिखा है, वहीं आरक्षक का बैंक खाता, चेकबुक, आरक्षक का आइकार्ड, डेबिट कार्ड, गैस कार्ड मिला है। इसके अलावा आरक्षक ने एक आवेदन एसपी के नाम पर लिखा था, जिसमें तखतपुर थाने से सकरी स्थानांतरित करने की बात लिखी है। पुलिस ने इस आवेदन को भी जब्त कर लिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

केबल कारोबारी सहित 9 डायरेक्टरों की याचिका खारिज

बिलासपुर। केबल व्यवसायी अशोक अग्रवाल व उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल, संजय खन्ना समेत 9 डायरेक्टरों के खिलाफ प्रार्थी डायरेक्टर ने 10 जून 2020 को रायपुर के देवेन्द्र नगर थाने में 68 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत दर्ज कराई, जिसपर पुलिस ने धारा 409, 420, 120 - बी 34 के तहत मामला दर्ज किया था, वहीं बाद में आईपीसी की धारा 467, 468, और 471 के तहत अन्य अपराध भी जोड़े गए थे। अब आरोपियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राहत अर्जी दाखिल की थी और उसे रद्द करने की मांग की, जिसपर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपों की पुष्टि हो रहे हैं, इसलिए चार्जशीट अनुसार कार्रवाई होगी। बता दें कि 68 करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला है, इसमें हैथवे सी. सी. एन मल्टीनेट प्रा. लि. के डायरेक्टर बिलासपुर निवासी अशोक अग्रवाल, पुत्र अभिषेक अग्रवाल, संजय खन्ना, दुलाल बैनर्जी, मयुर गोविंद भाई कनानी, सुधीर सरीन, सुनील सेठी, राजेश कुमार मितल ने मिलकर कंपनी को चूना लगाया था।

प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रावीण्य सूची जारी

जगदलपुर। समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्षितिज-अपार संभावनाएं के अंतर्गत जिले के दिव्यांग मेघावी छात्र-छात्राओं को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2023-24 के तहत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु एकीकृत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन कार्यालय जिला पंचायत जिला बस्तर के सूचना पटल पर किया गया है। उक्त प्रावीण्य सूची के संबंध में किसी भी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को दावा-आपत्ति हो तो वे 12 अगस्त 2024 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण जगदलपुर जिला बस्तर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा।

प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा को नहीं मिली अनुमति

लोरमी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में भी कथा और भीड़ वाले कार्यक्रमों की अनुमति देने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पंडित प्रदीप मिश्रा की 2 व 3 अगस्त को लोरमी में शिवपुराण कथा होने वाला था लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण एसडीएम ने इसकी अनुमति देने से आयोजकों को इंकार कर दिया है। सीहोर वाले पंडित के नाम से मशहूर पंडित मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि लोरमी में आयोजन समिति कि ओर से मांगी गई अनुमति को लोरमी एसडीएम ने अस्वीकार करते हुए फिलहाल रोक दिया है। उनका कहना है कि जिस जगह पर कथा का आयोजन होना है वहां पर व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में किसी भी तरह के हादसे की स्थिति बन सकती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले में छह विभागों से रिपोर्ट मांगी गई थी, इसके बाद यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की यह कथा 2-3 अगस्त से लोरमी में होने वाली थी।

292 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त भारत सरकार ने दिया प्रमाणपत्र

महासमुंद। टीबी मुक्त भारत के लिए चलाया जा रहा अभियान अब धरातल पर दिखने लगा है। इस अभियान के परिणामस्वरूप महासमुंद जिले की 292 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने जहां पंचायतों को 'टीबी मुक्त पंचायत' का प्रमाण पत्र दिया है, वहीं स्वास्थ्य अमला सहित ग्रामीण भी इस उपलब्धि से खुश हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले को 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों (स्ड्डत्र) द्वारा निर्धारित समय सीमा 2030 से पांच वर्ष पहले हासिल करने का है। जिले में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच जिले के 551 पंचायतों मे से 292 पंचायतों का चयन कर संभावित ग्राम पंचायतों में प्रति हजार जनसंख्या पर 30 लोगों की जांच की गई। टीबी उन्मूलन के इस अभियान में जिले की स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर मेहनत की है।

करंट की चपेट में आई खेत में काम कर रही महिला

जगदलपुर। जगदलपुर के बकावंड ब्लॉक के ग्राम बागरिया में काम करने के दौरान एक बुजुर्ग महिला को करंट लग गया, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में डायल 112 की मदद से सीएचसी बकावंड लाया गया। जहां उसे बेहतर उपचार के लिए भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बकावंड थाना क्षेत्र के ग्राम बागरिया पीड़िता गुरुबारी गंगाय पति लोकनाथ गंगाय 50 वर्ष घर के खेत में काम करने गई थी। खेत में काम करने के दैरान करंट की चपेट में आ गई। लोगों ने देखने के बाद डंडा मार कर महिला को अलग किया। इस घटना के बाद महिला बेहोश हो गई थी, जिसे खेत से बाहर निकाल कर मोटरसाइकिल की मदद से अस्पताल ले जा रहे थे। घटना की जानकारी लगने के बाद डायल 112 को बुलाया गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश पीड़िता को 112 वाहन में बैठाकर परिजनों के साथ उपचार हेतु सीएचसी बकावंड ले जाकर भर्ती किया गया।

28 लाख 81 हजार के ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 6 गिरफ्तार

जगदलपुर। जिले के थाना नगरनार पुलिस ने अपराध क्र.89/2024 के प्रार्थी से फर्जी डीमेट अकाउण्ड द्वारा स्टॉक के नाम पर निवेश कराकर प्रार्थी से विभिन्न चरणों में एवं विभिन्न माध्यम से कुल 28 लाख 81 हजार 104 रूपये की ठगी करने वाले 6 आरोपियों जमशेद अहमद फारूकी पिता शब्बीर अहमद फारूकी निवासी गोमतीनगर गुजरात, प्रवीण खटीक पिता राजू भाई खटीक निवासी अहमदाबाद गुजरात, राकेश पहाडिया पिता गौरीशंकर पहाडिया निवासी अहमदाबाद गुजरात, रमेश आर. पंचाल पिता रेवन दास निवासी रिंगरोड अहमदाबाद, राकेश राजपूत पिता राजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी अहमदाबाद गुजरात, सुश्री ट्वीकल शर्मा पिता प्रमोद शर्मानिवासी गुजरात हाउसिंग बोर्ड पुलिस लाईन सरसपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियें के कब्जे से 3 नग की-पेड मोबाईल, 5 नग टच स्क्रीन मोबाईल, 3 नग

स्वाईप मषीन, 2 नग स्केनर मषीन (आईडीएफसी बैंक एवं इन्डसण्ड बैंक), 11 नग एटीएम कार्ड, 2 नग पासबुक, 3 नग चेक बुक, 6 क्रेडिट कार्ड एवं पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज बरामद कर बस्तर पुलिस द्वारा अब तक 35 लाख रू. होल्ड कराया जा चुका है। आज सोमवार को थाना नगरनार में आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 मई 2024 को प्रार्थी अजीत कुमार ठाकुर पिता स्व. विजय कुमार ठाकुर निवासी एससी. जामुल जिला दुर्ग हाल पता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगदलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके फेसबुक अकाउण्ट में इंडियन स्टॉक ऑफिस वीआईपी 76 का लिंक देखकर व्हाटसएप ग्रुप मे मेम्बर बना तथा धन निवेश कर लाभ कमाने के लिए आईसीआईसीआई. सिक्योरिटी इंटरनेशनल इन्वेस्ट नामक एप डाउनलोड किया। प्रार्थी अजीत कुमार उक्त एप के द्वारा डेली रिव्यु देने पर प्रतिदिन पांच हजार रूपये खाते में जमा होने से अपर सर्किट स्टॉक, आईपीओ. में निवेश करना शुरू किया, जिससे प्रार्थी को कुछ धन लाभ होने पर प्रार्थी द्वारा 85 हजार रूपये निकाल लिया गया। उक्त प्रक्रिया में विश्वास होने पर एप के माध्यम से अठाईस लाख इक्यासी हजार एक सौ चार रूपये उस ऐप पर इन्वेस्ट किया जिसमें उसे लाभ दिखा परन्तु विड्राल करने पर इनको कोई रकम प्राप्त नही होने पर फ्रॉड होने की जानकारी हुई।

भुगतान प्राप्त नहीं होने संबंधी जानकारी देने पर सायबर ठगी होने की रिपोर्ट पर थाना नगरनार में 16 मई 2024 को अपराध क्र. 89/2024 धारा 420 भादवि. 66 (डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सायबर सेल के मदद से कुल 6 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर अहमदाबाद गुजरात थाना गोमतीपुर का निवासी होना बताये एवं प्रार्थी के निवेश का धन अपने खाते में प्राप्त कर ठगी करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति के नाम पर भिन्न-भिन्न खाता खुलवाकर एवं निवेश की धन राशि आहरित कर विदेश में भेजना स्वीकार किया गया, जिसकी लेन-देन की पुष्टि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं एवं विवेचना जारी है। आरोपियों के द्वारा उपयोग किये गये नम्बर एवं अकाउण्ट नम्बर साइबर पोर्टल में दर्ज करने पर देश के अन्य राज्यों में इनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज हैं।

राज्य तैराकी प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में रायपुर चैंपियन

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का खिताब बिलासपुर कार्पोरेशन ने जीता है। सब जूनियर प्रतियोगिता का खिताब रायपुर की टीम ने अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता तीन दिन तक चली।

छत्तीसगढ़ राज्य तैराकी प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 212 इवेंट हुए। जूनियर वर्ग में बिलासपुर कॉर्पोरेशन की टीम ने दम दिखाया। प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए रायपुर की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया। इसमें बिलासपुर जिला की टीम को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन पर भिलाई नगर निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी दिया।

आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने कहा इस तरह के इवेंट ज्यादा से ज्यादा कराए जाने चाहिए। अवसर मिलने पर ही बच्चों की प्रतिभा सामने आती है।

छत्तीसगढ़ तैराकी संघ महासचिव सहीराम जाखड़ ने कहा तैराकी के सीमित संसाधनों के

बावजूद भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश की टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम आगे होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेंगी।

छत्तीसगढ़ में लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग शहरों में इवेंट कराए जा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि इससे न सिर्फ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही है बल्कि उन्हें अपनी तैयारियों को परखने के साथ ही और बेहतर करने की प्रेरणा मिल रही है।

संक्षिप्त समाचार

सांसद संतोष पांडे लोकसभा में पार्टी के सचेतक नियुक्त

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने उन्हें लोकसभा में पार्टी के सचेतक (व्हीप) का कार्यभार सौंपा है। पार्टी संसदीय सचिव डॉ. शिव शक्ति नाथ बख्शी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सचेतकों की लिस्ट सौपी है। जिसमें बीजेपी ने पार्टी के 240 सांसदों में से 16 को सचेतक की जिम्मेदारी दी है। वहीं बिहार के सांसद डॉ.संजय जायसवाल को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली है।

बढ़ते अपराध को लेकर सभापति प्रमोद दुबे का जन चेतना अभियान जारी

रायपुर। शहर में बढ़ते अपराध एवं बिजली

बिल को लेकर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने सामाजिक जनचेतना अभियान के 9वें दिन महामाया मंदिर वार्ड में भ्रमण करते हुए आमजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और हस्ताक्षर लेकर अगले कुछ दिनों के भीतर बढ़ा आंदोलन करने की बात कहीं। सभापति प्रमोद दुबे ने बताया कि कांग्रेस की सरकार की थी तब तक छत्तीसगढ़वासियों कों हाफ बिजली बिल का लाभ मिल रहा था और उनकी सरकार ने कभी भी बिजली बिल बढ़ोत्तरी नहीं की। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है उन्होंने तत्काल बिजली बिल में फिर से 9.59 प्रतिशत फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ोत्तरी कर दी है जिसके कारण बिजली बिल डबल आना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम तो आसमान तो छू ही रहे है, खाने - पीने की चीजें भी 38 प्रतिशत बढ़ गई है अब और बढ़ोतरी कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसके साथ ही रायपुर शहर में आए दिन चाकूबाजी- लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ते जा रही है जिससे आमजन काफी परेशान है। इन्हीं सब मांगों को लेकर वे पिछले 9 दिनों से शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर आमजनों से मुलाकात कर उनकी राय लें रहे और आने कुछ दिनों के भीतर वे सरकार को जगाने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले है।

अंबिकापुर-बिलासपुर-रायपुर के बीच चलेगी फ्लाइट, सेवा जल्द होगी शुरू

रायपुर। उड़े देश का आम नागरिक 'उड़ान' योजना के तहत जल्द ही अम्बिकापुर से बिलासपुर एवं रायपुर को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू होंगी। उड़ान 4।2 के अंतर्गत अम्बिकापुर-बिलासपुर-अम्बिकापुर एवं अम्बिकापुर-रायपुर अम्बिकापुर मार्ग में उड़ानों का संचालन मेसर्स 'फ्लाय बिग' को अवार्ड किया गया है। कंपनी इस सेक्टर में 19 सीटर विमान का संचालन करेगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अम्बिकापुर एयरपोर्ट को मार्च से ही थ्री सी वीएफआर लाइसेंस मिला है। इसके तहत वहां से दिन में ही 72 सीटर विमान का संचालन किया जा सकता है। कंपनी ने अभी उड़ान का शेड्यूल जारी नहीं किया है। शेड्यूल के एप्रूवल के बाद ही उड़ानों का संचालन शुरू होगा। बता दें कि प्रदेश में रायपुर के बाद जगदलपुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। आरसीएस योजना के तहत उड़ानें शुरू होने के बाद अम्बिकापुर प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट होगा जहां से हवाई सेवाओं का संचालन किया जाएगा।

बजरंग अग्रवाल ने अपर मंड़ल रेल प्रबंधक (परिचालन) रायपुर का पदभार ग्रहण किया

रायपुर। श्री बजरंग अग्रवाल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के नये अपर मंड़ल रेल प्रबंधक (परिचालन) होंगे। श्री बजरंग अग्रवाल भारतीय रेलवे स्टोर सेवा - 2005 बैच के अधिकारी है। इससे पूर्व श्री बजरंग अग्रवाल पश्चिम रेलवे में उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (प्रशासन) पद पर कार्यरत थे। श्री अग्रवाल ने सोमवार शाम को अपर मंड़ल रेल प्रबंधक (परिचालन) रायपुर का पदभार ग्रहण किया। श्री बजरंग अग्रवाल को वर्ष 2015 में महाप्रबंधक रेल सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। इन्होने आई आई एस सी बेंगलुरु से एम. टेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) की उपाधि हासिल की है । वर्ष 2017 में जापान से हाई स्पीड ट्रेन की ट्रेनिंग भी की है। श्री बजरंग अग्रवाल पूर्व में सेंटर रेलवे में डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर और उप मुख्य सामग्री प्रबंधक मटुंगा वर्कशॉप मुंबई के पदो पर भी कार्य कर चुके है।

मुख्यमंत्री साय ने मनु भाकर व सरबजोत को पदक जीतने पर दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर सुश्री मनु भाकर एवं श्री सरबजोत को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड स्पर्धा में आप लोगों ने देश के लिए गौरव हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि सुश्री मनु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में दो पदक हासिल किए हैं यह विशेष उपलब्धि है।

पीएम आवास योजना : निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवास के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को हितग्राहियों को स्वीकृत आवासों का आबंटन करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जीएफआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट सहित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के करीब 156 नगरीय-निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक हितग्राहियों द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) के अंतर्गत 937 परियोजनाओं में एक लाख 50 हजार 898 आवास स्वीकृत किए गए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजु एस., विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य शामिल हुए।

किसानों को 8.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित

रायपुर। प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों की बोनी के लिए सरकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से सुगमता के साथ प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों के 8 लाख 64 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किए गए हैं, जो कि राज्य में बीज की मांग का 88 प्रतिशत है। गौरतलब है कि राज्य में खरीफ की विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की कुल मांग 9 लाख 78 हजार क्विंटल है, इसके विरूद्ध 9 लाख 78 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज भण्डारण किया जा चुका है, जो कि बीज मांग का 97 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 8.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है.

सक्रिय राजनीति में उतरूंगा या नहीं फैसला पार्टी करेगी : बैस

रायपुर । महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे रमेश बैस मंगलवार को रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि, 5 सालों में तीन राज्यों का राज्यपाल रहा। मुझे खुशी है कि, मेरा पूरा कार्यकाल बेदाग रहा और एक भी आरोप नहीं लगा। यही राज्यपाल के रूप में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सक्रिय राजनीति में उतरने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, सक्रिय राजनीति में उतरूंगा या नहीं इसका फैसला पार्टी करेगी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो आदेश होगा, वहीं काम करूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर उन्होंने कहा कि, राहुल पहले महाभारत तो पढ़ लें उसके बाद ऐसा कोई बयान दें। उन्होंने आगे कहा कि, पार्टी ने मुझे काफी कुछ दिया है और मैं काफी सौभाग्यशाली हूं कि, पार्टी ने मुझे इतना अवसर दिया है। कई कार्यकर्ता अपना जीवन खपा देते हैं. लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है।

छत्तीसगढ़ में अब तक हुई 551.3 मिमी वर्षा

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 551.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 30 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई। वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1325.5 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 205.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

शिक्षक भर्ती 2023 के अभ्यर्थी भटकने को मजबूर

रायपुर। शिक्षक भर्ती 2023 के रिक्त पदों में भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर से प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने छठी सूची में योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने की मांग की है। साथ ही इसके संबंध में आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम अरुण साव और संचालय के सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अभ्यर्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में पूर्व सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय (शिक्षा विभाग) द्वारा 4 मई 2023 को 12489 पदों पर भर्ती 2023 का सीधी भर्ती का नोटीफिकेशन जारी किया गया था। इसकी परीक्षा 10 जून 2023 को सम्पन्न हुई और परीक्षा परीणाम 2 जुलाई 2023 को जारी हुआ। जिसमें वर्ग 02 शिक्षक के 5772 पद और व्याख्यता वर्ग 01 का 432 पद को पूर्ण कराने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था जो कि एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया इसी को लेकर वर्तमान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते यह भर्ती प्रक्रिया पांच माह विलम्ब हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है शिक्षक भर्ती 2023 की बचे रिक्त पदों पर कौशलिंग कराकर यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संचनालय के सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं।अब छत्तीसगढ़ राज्य अजा-जजा आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से मुलाकात कर उनसे भी मांग करेंगे।

डॉक्टर ने बच्चे का जटिल ऑपरेशन कर बचाई आंखों की रोशनी

■ **खुशी में मां ने डॉक्टर के नाम पर किया बच्चे का नामकरण**

रायपुर। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। यहां एक मां अपने बच्चे की आंख की गंभीर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर के सेवाभाव से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने बच्चे का नाम डॉक्टर के नाम पर कर दिया। हम बात कर रहे हैं साईं बाबा हॉस्पिटल के संचालक डॉ। आशीष महोबिया की, जिन्होंने गरीब परिवार के एक बच्चे की आंख की गंभीर बीमारी का निशुल्क इलाज कर बच्चे के आंख की रोशनी बचाई।

लेजर ट्रीटमेंट जैसे महंगा माने जाने वाले इलाज को निशुल्क कर डॉ। आशीष महोबिया ने गरीब परिवार के दिल में खास जगह बना ली है। बच्चे की मां डॉक्टर आशीष महोबिया की सदाशयता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने बच्चे का नाम बदलकर आशीष रख दिया। बलौदाबाजार जिले के रवान गांव में रहने वाले सुनील टोप्पो और धनलक्ष्मी को सन 2016 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे का जन्म रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में हुआ, जहां जांच में पता चला कि उसकी आंखों में कोलोस्टोमी ओपनिंग एंड क्लोजर नामक बीमारी का थर्ड स्टेज है। गरीब मां-बाप के पास इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर डॉ. आशीष महोबिया ने बच्चे के माता-पिता से संपर्क कर निशुल्क लेजर ट्रीटमेंट करने का आश्वासन दिया। डॉ। आशीष ने परिजनों को बच्चे की बीमारी की गंभीरता के बारे में बताया और कहा कि बच्चे का तुरंत लेजर के जरिए ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह पर परिजनों ने बच्चे का लेजर आपरेशन करने पर सहमति जताई और डॉ. आशीष ने सफलतापूर्वक लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बच्चे की जटिल बीमारी का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी बचा ली गई, जिसके बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे की मां धनलक्ष्मी डॉ। आशीष के मानवीय रवैये से इतनी प्रभावित हुईं कि उसने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए बच्चे का नाम आशीष ही रख दिया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को दी गई विदाई राजभवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। वे मंगलवार को भुवनेश्वर (ओड़िशा) के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी मौजूद थीं।

राज्यपाल के विदाई से पहले उन्हे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की।इसके बाद सभी को आशीर्वाद दिया।इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से सभी लोग हमेशा समृद्ध और सुखी रहे। राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पवर्षा कर हरिचंदन का अभिवादन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय एवं उपसचिव हिना नेताम सहित राजभवन समेत राजभवन के सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ से पहले विश्वभूषण हरिचंदन आंध्रप्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा राज्य के नेता रह चुके हैं।

जिन्होंने भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से पांच बार विधायकी की है। अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई 2019 को राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उस समय मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका आज लेंगे शपथ

रायपुर/गुवाहाटी। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। रायपुर में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल 31 जुलाई को सुबह 10.15 बजे रायपुर स्थित राजभवन में शपथ लेंगे। राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा रमेन डेका को राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे।

रमेन डेका वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे। विश्वभूषण हरिचंदन फरवरी 2023 को राज्यपाल बने थे। रमेन डेका बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के पूर्व सांसद रह चुके हैं। रमेन डेका की गिनती असम के तेज तर्रार नेताओं में होती है। उन्हें राजनीति के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है।

रमेन डेका के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य में नए आरक्षण बिल जो अरसे से लटका हुआ है उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई है।

रमेन डेका भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। वह राज्यपाल के प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले आठवें असमिया हैं। इससे पहले शनिवार देर रात को राष्ट्रपति ने कई राज्यों के राज्यपाल बदलने का आदेश जारी किया। उसके तहत रमेन डेका के छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति ने जारी किया। कुल 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय और असम राज्य शामिल है।

डीए, एचआरए और सैलरी को लेकर आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 6 अगस्त से अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं। इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

छत्तीसगढ़ में लगभग 112 कर्मचारी संगठन है, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 4 सूत्रीय मांग में महंगाई भत्ता, एरियर्स सहित 4 सूत्रीय मांग शामिल है। अगस्त क्रांति यानी 6 अगस्त से पहला चरण शुरू होगा। जिसमें इंद्रावती भवन से लेकर मंत्रालय तक मशाल रैली निकाली जाएगी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया 4 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 4 चरणों में आंदोलन करेंगे। जिसमें दो चरण अगस्त के महीने में और दो चरण सितंबर के महीने में किया जाएगा। पहले चरण में अगस्त क्रांति यानी 6 अगस्त को प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी रायपुर पहुंचकर इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक मशाल रैली निकालेंगे। दूसरा चरण 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक प्रदेश के विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। तीसरा चरण 11 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में जिला, ब्लॉक और तहसील में रैली निकाला जाएगा। चौथा चरण 27 सितंबर को प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। भाजपा की घोषणा पत्र के अनुसार मोदी की जो गारंटी पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग फेडरेशन ने की है। कमल वर्मा ने बताया प्रदेश के कर्मचारियों को देय तिथि से 4 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता मिले। जुलाई 2019 से डीए का समायोजन जीपीएफ खाते में हो। प्रदेश में चार स्तरीय वेतनमान लागू हो, 240 दिन के अर्जित अवकाश को 300 दिन किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) दिया जाए। अधिकारी कर्मचारी संघ ने दावा किया कि 4 चरणों के आंदोलन के बाद यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो कोर कमेटी की बैठक आयोजित करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया जाएगा।

पॉवर कंपनी में अनामिका मण्डावी को प्रकाशन अधिकारी का वेतनमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में पदस्थ सहायक प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मण्डावी को उच्च वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा जारी कर किया गया है। वे कार्यालय अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) में ही पदस्थ रह कर अपने पद एवं दायित्व का निर्वाह करेगी।

श्रीमती अनामिका मण्डावी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी में वर्ष 2015 में सहायक प्रकाशन अधिकारी के रूप में चयनित हुई थी। उन्होंने हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में पदस्थापना के साथ-साथ अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तत्पश्चात् उनकी योग्यता एवं प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पॉवर कंपनी मुख्यालय डंगनिया में पदस्थ किया गया। वे जनसम्पर्क विभाग के अन्य कार्यों के अतिरिक्त मासिक पत्रिका संकल्प में संपादकीय सहयोगी के रूप में संलग्न है। पदोन्नति के पद का वेतनमान मिलने के अवसर पर आज उनका कार्यालय में अभिनंदन किया गया।

हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस पटरी से उतरी, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द

रायपुर। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन 12810 झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में डिरेल हो गई है। ट्रेन की 18 बोगी पटरी से उतर गई है। इस हादसे में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 2 यात्रियों की मौत हो गई है, कई यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल होने से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 15 ट्रेनों का रूट चेंज किया गया है। 2 ट्रेनें रद्द की गई है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी समीर कान्त माथुर ने बताया कि हावड़ा मेल 12810 के पटरी से उतरने के बाद 15 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। कुछ ट्रेनों को भद्रक, खुर्दा रोड और झारसुगुडा और कुछ ट्रेनों को पुरलिया, खटिया और राउरकेला रोड से चलाया जा रहा है। इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस को बिलासपुर और इतवारी के बीच ही चलाया जाएगा। शालीमार लोकमान्य तिलक को कैंसिल किया गया है। डायवर्टेड रूट से आने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किए गए हैं। सभी बड़े स्टेशनों जैसे बिलासपुर, रायगढ़, बृजराजनगर, चांपा, खरसिया रायपुर, भाटापारा, दुर्ग, राजनांदगांव, भंडारा, गोंदिया में लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए खानपान और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का रूट चेंज

12262 हावड़ा - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जेसीओ 30।07।24 खड़गपुर - भद्रक - खुर्दा रोड - अंगुल - झारसुगुड़ा रोड - आईबी के माध्यम से।

12810 हावड़ा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 30-07-24 को खड़गपुर-मिदनापुर-आद्रा-बोकारो स्टील सिटी-कोडरमा-नीमडीह-राउरकेला से शुरू होगी।

12834 हावड़ा - अहमदाबाद जेसीओ 29।07।24 चांडिल - पुरुलिया - हटिया - राउरकेला के रास्ते।

18477 पुरी - योग नगरी ऋषिकेश जेसीओ 29।07।24 चांडिल - बोकारो स्टील सिटी - गोमो के रास्ते।

18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार जेसीओ 28।07।24 राउरकेला - हटिया - पुरुलिया - टाटानगर के रास्ते, डीएन ट्रेनें (हावड़ा की ओर)।

12859 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - हावड़ा जेसीओ 29।07।24 राउरकेला - हटिया - पुरुलिया - टाटानगर के रास्ते।

12860 हावड़ा - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 30-07-24 को टाटानगर - चांडिल - पुरुलिया - कोडरमा - नीमडीह - राउरकेला के रास्ते शुरू होगी।

12833 अहमदाबाद - हावड़ा जेसीओ 28।07।24 राउरकेला - हटिया - पुरुलिया - टाटानगर के रास्ते।

13287 दुर्ग-आरा जेसीओ 30।07।24 वाया राउरकेला-नीमडीह-मुरी-कोडरमा-बोकारो स्टील सिटी-गोमो-आसनसोल।

13288 आरा-दुर्ग जेसीओ 29।07।24 आसनसोल-गोमो-बोकारो स्टील सिटी-कोडरमा-मुरी-नीमडीह-राउरकेला के रास्ते

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रद्द ट्रेनें

18110 इतवारी-टाटानगर जेसीओ 30।07।24 बिलासपुर टाटानगर के बीच रद्द।

18109 टाटानगर - इतवारी जेसीओ 30।07।24 टाटानगर - बिलासपुर के बीच रद्द।

18030 शालिमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन रद्द।

लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं राजनीतिक टकराव

राज कुमार सिंह

संसद के बजट सत्र की हंगामेदार शुरूआत ने इन आशंकाओं को सही साबित कर दिया है कि 18 वीं लोकसभा और अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार की डगर आसान नहीं होगी। संसद के अंदर और बाहर, सरकार को कठघरे में खड़ा करने का कोई मौका विपक्ष चूकता नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा न मानें लेकिन बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे छूट जाने और सरकार की स्थिरता के लिए तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल यूनाइटेड , (जद-यू) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) जैसे सहयोगियों पर निर्भरता का असर साफ दिख रहा है। 543 की लोकसभा में 240 सीटों पर सिमट जाने से भाजपा का डगमगाया आत्मविश्वास नई संसद के पहले विशेष सत्र में भी साफ दिखा था, जब 234 सीटें जीत लेने वाला विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' हर मौके पर सरकार पर हमलावर नजर आया। 10 साल बाद संसद में ऐसा नजारा दिखा। ध्यान रहे कि 10 साल बाद ही विपक्ष को, राहुल गांधी के रूप में नेता प्रतिपक्ष मिला है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी बनाम राहुल का जो टकराव नजर आया था, वह बजट सत्र में और भी ज्यादा तीखा होता दिख रहा है। बेशक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बीच मंत्रियों द्वारा लगातार टोकाटाकी और प्रधानमंत्री के जवाब के बीच विपक्ष की लगातार नारेबाजी को उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा लगता है कि संसदीय परंपरा और मर्यादा अब बीते जमाने की बातें बन कर रह गई हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि हम संसद के बजट सत्र में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच उसी टकरावपूर्ण व्यवहार का विस्तार देख रहे हैं। कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि संसद देश और समाज के हित में काम करने के लिए है, न कि दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि सत्तापक्ष अपने बजट को देश के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज बता रहा है तो विपक्ष उसे दिशाहीन करार दे रहा है, पर बिहार और आंध्र प्रदेश को विभिन्न मदों में लगभग एक लाख करोड़ की विशेष सहायता की घोषणाओं ने वर्ष 2024-25 के बजट को राजनीतिक 'एंगल' दे दिया है। इसी को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने इसे 'कुर्सी बचाओ बजट' करार दिया और संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। भाजपा के बहुमत से 32 सीटें पीछे 240 पर सिमट जाने से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह तीसरी केंद्र सरकार, खासकर तेदेपा और जद (यू) के समर्थन पर टिकी है। दोनों ही राज्य लंबे समय से अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मांगते रहे हैं। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तो इसी मांग पर 2018 में राजग छोड़ कर विपक्ष के खेमे में चले गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अलग-अलग मुद्दों पर कई बार पाला बदल चुके हैं। इस बार जब तेदेपा और जद (यू), राजग में लौटे तो राजनीतिक जरूरतों के अलावा सरकार बनने पर विशेष आर्थिक मदद की उम्मीद भी बड़ा कारण रही। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मोदी सरकार ने बजट से पहले ही तेदेपा और जद (यू) को यह संदेश दे दिया, लेकिन फिर भी बजट में बिहार और आंध्र को कई मदों में मिला कर लगभग एक लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का ऐलान बताता है कि दबाव में और सत्ता की खातिर यह रास्ता निकाला गया है। इतनी बड़ी राशि देने के लिए कहीं-न-कहीं बड़ी कटौतियां भी की गई होंगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा तीखे प्रहारों के बीच वित्त मंत्री ने सफाई अवश्य दी कि बजट भाषण में नाम न लिए जाने का यह अर्थ हरगिज नहीं कि अन्य राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, पर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर गया तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को केंद्रीय मदद पर श्वेत पत्र की मांग कर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। नोटबंदी और प्रधानमंत्री का उल्लेख करने पर स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा टोके जाने पर अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह उन्हें निष्पक्षता की याद दिलाई उससे तो साफ हो गया कि उनके लिए भी सदन चला पाना पिछली लोकसभा जितना आसान नहीं होगा। अभिषेक से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अपने-अपने अंदाज में स्पीकर यानी आसन की सर्वोच्चता और निष्पक्षता की ओर इशारा कर निशाना साध चुके हैं। याद रहे कि 17वीं लोकसभा में रिकार्ड संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का असर बजट के पारित होने पर शायद न भी पड़े लेकिन संसद की कार्यवाई पर पड़ना तय है। संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।

अपनी ही उलझनों में फंसा पाकिस्तान

मरिआना बाबर

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा अपनी कलम के एक झटके से फरवरी में हुए चुनाव को रद्द कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, 90 दिनों के भीतर फिर से चुनाव कराने होंगे। यह डर न केवल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के मन में है, बल्कि सुरक्षा प्रतिष्ठान (सेना) भी इससे काफी आशंकित है, क्योंकि अदालत में इमरान खान (जो फिलहाल जेल में हैं) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ द्वारा दायर मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है।

फिलहाल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अवकाश पर है और सितंबर में कभी भी अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। काजी ईसा इस साल 25 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें सेवा विस्तार का प्रस्ताव दिया जाता है, तो वे उसे स्वीकार करने में रुचि नहीं रखते हैं। अब पाकिस्तान और विदेश में भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि फरवरी में हुए चुनाव के नतीजे निष्पक्ष नहीं थे और सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा इमरान खान एवं उनकी पार्टी को स्पष्ट जीत से वंचित रखने के लिए हर गलत कदम उठाया गया।

पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को इसलिए भारी मत दिया, क्योंकि उनके पास जनाधार था। इसके अलावा, लोग शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की पिछली सरकार से तंग आ चुके थे, जिसके पीछे भयंकर महंगाई और बेरोजगारी प्रमुख वजह थी। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई बड़े और वरिष्ठ नेता

चुनाव हार गए। यहां तक कि पीएमएल एन के अध्यक्ष नवाज शरीफ भी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। चुनाव में पीएमएल-एन के खराब प्रदर्शन के कारण नवाज शरीफ ने फिर से प्रधानमंत्री बनने का विचार त्याग दिया। पाकिस्तान में इस समय संस्थाओं में तीखे एवं गंभीर मतभेद हैं। एक तरफ स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट है, जिसने हाल ही में विभिन्न मामलों में पीटीआई को भारी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के चलते पीटीआई को नेशनल असेंबली में सीटें वापस मिल गईं, जो चुनाव आयोग द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को दे दी गई थीं। शुक्र है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है। दूसरी तरफ, सुरक्षा प्रतिष्ठान स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट से नाराज है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इमरान खान या उनकी पार्टी पीटीआई को कोई राहत मिले।

वास्तव में, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान के खिलाफ कई मामले अदालतों में हैं और उन्हें जेल में रखने के लिए रातों-रात नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान का जेल से बाहर रहना, दोनों पक्षों के लिए खतरा है। अगर फिर से चुनाव होते हैं, तो इमरान खान दो तिहाई बहुमत से जीत हासिल करेंगे। सुरक्षा प्रतिष्ठान ने गलत कार्ड खेला। इमरान खान को प्रताड़ित करके और पूरे मुल्क में उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करके उन्होंने इमरान खान को सुपर हीरो बना दिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी संसद (दोनों दलों ने भारी बहुमत से समर्थन किया) और हाल ही में ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी इमरान खान का समर्थन किया है।

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और सुरक्षा प्रतिष्ठान एकमत हैं। इसलिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं कि वह सितंबर में क्या फैसला सुनाता है। चूंकि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए राजनीतिक उथल-पुथल के चलते मुल्क में अस्थिरता पैदा हो रही है। हालांकि आपातकाल घोषित करने या मार्शल लॉ थोपे जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि पाकिस्तान पहले भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका है। लेकिन यह 2024 है और अब ऐसा होना असंभव लगता है। लेकिन जैसा कि कई लोग पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है, खासकर ऐसे समय में, जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के फैसले देता है, तो शहबाज शरीफ सरकार नेशनल असेंबली में अपना दो तिहाई बहुमत खो देगी और वह अल्पमत की सरकार बन जाएगी, जिसका अर्थ यह होगा कि वह संविधान में कोई बदलाव नहीं कर पाएगी।

सुरक्षा प्रतिष्ठान भी शहबाज शरीफ सरकार से तंग आ चुका है, जैसा कि इस हफ्ते इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय राजनीति पर अधिक जोर दिया गया था।

इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें कई सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है। कई लोगों का मानना है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान राजनीतिक जोड़-तोड़ में इतना उलझा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। यह जनता के बढ़ते संदेह का भी कारण है, जो बन्नू विरोध प्रदर्शनों में दिखा। यह विडंबना है कि पाकिस्तानी सेना को मुल्क की जनता के गुस्से का निशाना बनना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक जाहिद हुसैन का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का राजनीतिक दबाव ही सुरक्षा प्रतिष्ठान को और अधिक विवादास्पद बना देगा। सवाल उठता है कि आखिर इस दबाव का उद्देश्य क्या था। ऐसे समय में प्रवक्ता की टिप्पणी के गंभीर राजनीतिक निहितार्थ हैं, जब मुल्क को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए राजनीतिक तापमान को कम करने की सख्त जरूरत है।

दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार की आलोचना की, जहां कुछ क्षेत्रों से आतंकवादियों को खदेड़ दिए जाने के बावजूद नागरिकों के लिए सही परिस्थितियां नहीं बनाई जा सकी हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण सेना का काम नहीं है। उन्होंने पिछले वर्ष नौ मई को बगावत में शामिल लोगों के खिलाफ मामले को नहीं बढ़ाने के लिए न्यायपालिका को भी दोष दिया। उन्होंने संघीय सरकार पर डिजिटल आतंकवाद पर नियंत्रण करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर सेना की तीखी आलोचना की जाती है। हालांकि सरकार ने पहले ही मुल्क में एक्स (ट्विटर) पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में फिलहाल यह अनुमान लगाना कठिन है कि पाकिस्तान में ये सारे मामले अंततः कैसे सुलझेंगे।

एकात्मता के स्वर

सरस्वती नदी

श्रंधकासुर की पीड़ा से देवों को पुका करने के लिये -विष्णु-महेश तीनों के एकत्रीकरण से उनके तेज से शुक्ल कृष्णवराणी एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। जिस ने तीन रूप धारण कर लिये। मया के अंश ब्राह्मी सरस्वती, विष्णु के अंश से रक्तवणी जैष्णवी लक्ष्मी और श्य के अंश से असित वर्ण रुवाणी कहलायी। एक समय सरस्वती ने यह जानकर कि विष्णु गंगा से ज्यादा स्नेह रखते है तो उन्होंने गंगा से भला-बुरा कहा, तब लक्ष्मी ने उन्हें समझाया, जिससे गंगा का पक्ष लेता जान सरस्वती ने उन्हें वृक्षरूपा और नदीरूपा होने का श्राप दे दिया। इस प्रश्य को देख गंगा ने सरस्वती को बाप देते हुए कहा तुम भी नदीरूपा हो मृत्युलोक में चली जाओ। इस बाप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाये, आये अंश से ब्रम्हा के भवन में पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। प्रत्येक ब्रम्हाण्ड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारम्भ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। ब्रम्हर्षि मार्कण्डेय के निवेदन करने पर हिमालय पर्वत के शिवालीक पहाड़ी के पाकर (प्लक्ष) की जड़ से सरस्वती नवी भावपय शुक्ल द्वादशी को प्रकट (प्रवाहित) हुई। सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात प्रदेशों को सींचती हुई पश्चिम सिन्धु सागर में मिलती है। इस नदी के गमन के रास्ते में पुष्पक, कुरुक्षेत्र, विराट, पुष्कर, अर्बुदारण्य, सिद्धपुर, प्रभास आदि प्रमुख तीर्थस्थान आते हैं। सरस्वती नदी रूप में जल प्रवाहित कर जहाँ जनकल्याण करती है वहीं वह बुद्धि प्रयाता देवी भी ऋग्वेदादि में कहीं गई है। वैदिक सरस्वती नदी के तट पर मनु, पांचाल, इक्ष्वाकु, चायमान, संवरण आदि राजाओं ने अपने राज्य, गण एवं यज्ञ परम्पराओं की वृद्धि की तथा सारस्वत सभ्यता का उन्नयन किया। वैदिक काल में यह नदी सर्वाधिक गतिशील उर्वराशक्ति की प्रेरिका नदीतमा के रूप में हिमालय से निकलकर आसमुद्रात बहने का उल्लेख है। इसका फैलाव आठ किलोमीटर रहा होगा। महाभारत काल में सरस्वती का प्रवाह कालीबंगा और अनूपगढ तक था। भगवान् बलराम ने उस समय तीर्थयात्रा की थी। प्राणी का उदय भी इसी सरस्वती के तट पर आज से एक करोड़ दस लाख वर्ष पहले हुआ था। उसी से सारी दुनिया का विकास हुआ। यह सारे अंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हैं। इसके किनारे केवल मनुष्य का जन्म ही नहीं बल्कि कृषि का प्रारंभ भी हुआ। यहीं पर सब प्रकार की सभ्यता का उन्नयन हुआ। यहीं पर लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षाएँ, यज्ञशालाएँ, ललित कलाएँ सहित अनेक प्रयोगशालाएँ स्थापित रहीं थीं। ऋग्वेद में इसे तीव्र वेगवती समुद्रगामिनी तथा नदियों की माता कहा गया है। इस नदी को गंगा से भी अधिक पवित्र व सिन्धु से अधिक विशाल वर्णित किया

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-6)

गतांक से आगे...

दूसरा - सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक अविशिष्ट-क्रम- जो विष्णु, मत्स्य, शिव, कूर्म, पद्म और श्रीमद्भागवत- आदि पुराणों में लिखा है। तीसरा वर्णसाम्यक्रम जो देवी-भागवत में लिखा है। यद्यपि यह तीनों नाम हमारे ही निर्धारित किये हुवे हैं तथापि क्रम-विन्यास की भिन्नता को समझने में ये पाठकों को पर्याप्त सहायता कर सकते हैं एतदर्थ यहाँ इनका निरूपण किया जाता है ।

विशिष्ट क्रम में जीव ब्रम्ह की व्यावहारिक भेद भावना को स्थिर रखते हुवे ब्रम्ह से ब्रम्हाण्ड का बनना और उसी में पुन: लीन हो जाना जिस प्रक्रिया से सम्पन्न होता है वह क्रम बताया गया है। अविशिष्क्रम में- जीव ब्रम्ह की पारमार्थिक ऐक्य-भावना को ध्यान में रखते हुवे ब्रम्ह का नाम रूप उपाधि द्वारा ब्रम्हाण्ड रूप में भासना, और अविद्यावृत्ति पूर्वक पुन: अपने आप में स्थिर होना - जिस प्रक्रिया से सम्पन्न होता है - वह क्रम बताया है। वर्णसाम्यक्रम में तात्विक पौर्वापर्य्य भावना को छोड़ कर यदृच्छा से केवल तुल्य वर्गों की समतानुसार अठारह नामों को गिन दिया है। अब इनका विशेष निरूपण किया जाता है। देवी भागवत को छोड़ कर प्राय: सभी पुराणों में पहिला पुराण ब्रम्ह है और अन्तिम पुराण ब्रम्हाण्ड है, जिससे यह सूचित किया है कि ब्रम्ह ही ब्रम्हाण्ड रूप में परिणत हो जाता है ! यह दृश्य ब्रम्हाण्ड ब्रम्ह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अस्तु। अत अन्य पुराणों का क्रम भी देखिये । आपने कभी शेषशायी भगवान् का चित्र अवश्य देखा होगा, यह एक वैज्ञानिक चित्र है जो देखने में साधारण होते हुवे भी गहरी फिलासफी से भरपूर है। हम यहाँ केवल उसके बहिरङ्ग रूप पर विचार करते हैं। क्षीरसागर समुद्र में शेषनाग की शैय्या पर भगवान् लेटे हुये हैं, उनकी नाभि में कमल पैदा हुआ है जिस पर बैठे हुये ब्रम्हा जी वेदपाठ कर रहे हैं। (**क्रमशः**)

साहित्य जगत की प्रेरणा है मुंशी प्रेमचंद

डॉ. वंदना सेन

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तरप्रदेश के वाराणसी शहर से चार मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद ने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलायी। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास का सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने नाटक, उपन्यास, कहानी, समीक्षा, लेख, संस्मरण संपादकीय आदि विधाओं में साहित्य का सृजन किया, पर उन्हें ख्याति कथाकार के रूप में प्राप्त हुई। अपने जीवनकाल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। प्रेमचंद्र ने सन् 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति के रूप में संबोधन किया। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणापत्र का आधार बना।

महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का साहित्य कालजयी है। उन्होंने देश और समाज के बारे में गंभीर चिंता करते हुए अपनी लेखनी चलाई है। समाज की जटिलताओं को कहानी और उपन्यासों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, उसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे आज भी समसामयिक लगती हैं। कहा जाता है कि साहित्य वही है जो हमेशा प्रासंगिक बना रहे। प्रेमचंद जी ने समाज आधारित साहित्य की रचना की। जो आज भी नवोदित साहित्यकारों के लिए एक सार्थक दिशा का बोध कराता है।

वास्तव में प्रेमचंद की रचनाएं समाज का दर्पण हैं। प्रेमचंद जी साहित्यकारों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। यह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का ही काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है, वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है। हमारे सद्भावों का संचार करता है। हमारी दृष्टि को फैलाता है।

प्रेमचंद ने केवल मनोरंजन के लिए साहित्य रचना नहीं की, बल्कि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को नयी रूपरेखा, नये आदर्शों में ढालने का प्रयास किया। उनके सृजन कर्म का उद्देश्य साहित्य के द्वारा समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देने और एक ऐसे शोषण विहीन सामज की रचना करना था, जिसका आधार स्वतंत्रता हो। प्रेमचंद अपने साहित्य रचना के माध्यम से इस उद्देश्य में सफल रहे हैं।

प्रेमचंद की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित थी। अलंकारों और मुहावरों ने उन्हें सजीवता प्रदान की। इनकी भाषा के कारण इनकी रचना के सभी पात्र व चरित्र हमारे समक्ष सजीव हो उठते हैं। यही इनकी भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। इनकी भाषा सहज सरल एवं बोधगम्य है। साहित्य एक विराट उद्देश्य को लेकर चलने वाली विधा है और उसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन को अधिक सूक्ष्मता एवं विस्तार से जांचा परखा जाता है। उपन्यास साहित्य की सशक्त एवं प्रवाहमय धारा है। मनुष्य चरित्र के अनेकानेक चित्र प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक विकल्प उपन्यासकार के पास ही होते हैं।

अमेरिकी लोकतंत्र पर मंडराते चिंता के बादल

राजेश बादल

घायल शेर की तरह दहाड़ रहे डोनाल्ड ट्रंपअमेरिका की राजनीति को अब कहां ले जाना चाहते हैं? वे कहते हैं कि अनुदार ईसाइयों ने उन्हें इस बार वोट दे दिया तो फिर कभी वोट देने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जाहिर है कि उनका यह कथन अमेरिका ही नहीं, समूचे वैश्विक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। केवल संविधान के मुताबिक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव करा लेना ही जम्हूरियत की निशानी नहीं है।

लेकिन इन दिनों लोकतंत्र की यही परिभाषा मान ली गई है। एक तंत्र जिस निर्वाचन प्रक्रिया से तहत अपना जनप्रतिनिधि चुनता है, उसे स्वभाव से भी लोकतांत्रिक होना आवश्यक होता है। क्या अमेरिका का भद्र लोक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की मंशा को समझने का प्रयास करेगा? यदि उनके इस कथन में छिपी खतरनाक चेतावनी को नहीं समझा तो अमेरिका ही नहीं, कई देशों को इसके प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठे और अनुचित कथनों के आधार पर संसार के किसी भी गपोड़ी राजनेता से होड़ ले सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक शोध के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए 30572 से अधिक झूठ बोले। झूठ का यह आंकड़ा प्रतिदिन औसतन 21 पर जाकर ठहरता है। एक दिन में जो सार्वजनिक जनप्रतिनिधि इतने झूठ बोले, क्या उस पर संसार का कोई सभ्य लोकतांत्रिक समाज भरोसा कर सकेगा? इसी कड़ी में टोरंटो स्टार ने जनवरी 2017 से लेकर जून 2019 तक ट्रंप के झूठों का संकलन किया और पाया कि

उन्होंने 5276 बार झूठ बोला। यह औसतन 6 झूठ प्रतिदिन है। ट्रंप को पराजित करने वाले बाइडन भी असत्य बोलने में उस्ताद हैं। उनके झूठ की कहानियां अमेरिका में प्रचलित हैं। स्थापित धारणा है कि लोकतंत्र सत्य और भरोसे की पूंजी से चलता है और झूठ बोलने वाले लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते।

कह सकते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा आधारित गणतंत्र की अवधारणा से पीछे हट रहा है। सवाल इसका नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या नहीं। वे जीतें या पराजित हों, विश्व बिरादरी की चिंता इस बात पर है कि संसार के सबसे आधुनिक और संपन्न लोकतंत्र के मतदाता क्या एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में अपने मुल्क की बागडोर सौंपेंगे, जो स्वभाव से ही अलोकतांत्रिक है। ट्रंप स्वभाव से अलोकतांत्रिक हैं - इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुझे उनके हालिया बयान का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। उनका पिछला कार्यकाल भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वे केवल पैसे की भाषा समझते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि औसत अमेरिकी नागरिक के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।

उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका अपने जिस लोकतंत्र की वकालत करता दिखाई देता है, उस पर सारा संसार क्या सोचता है। लेकिन उनके कथन या व्यवहार से फर्क उन देशों को पड़ता है, जो उस पर बहुत कुछ निर्भर दिखाई देते हैं। इनमें कनाडा, यूरोपीय देश और अन्य पिछलग्गू मुल्कों के विचार का समय अवश्य आ गया है कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक धुरी के रूप में उनके हितों की हिफाजत करने की जगह छोड़ता जा रहा है। आज का अमेरिका वह नहीं रहा है, जो विश्व को अंतरराष्ट्रीय मान्य संस्थाओं से जोड़कर रखता था, द्विपक्षीय मतभेद की स्थितियों में प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर निर्णायक सरपंची राय प्रकट करता था और अपने प्रभाव से एक लचीला संतुलन बनाकर रखता था। आज का अमेरिका विकासशील देशों को सिर्फ इसलिए जोड़कर रखता है कि वे उसके लिए एक बाजार मात्र हैं। उन बाजारों से धन मिलता है।

जहां से धन नहीं मिलता, वहां वह कुटिलतापूर्वक अपने मित्र राष्ट्रों की मदद से अपनी आर्थिक सेहत सुनिश्चित करता है। ब्रिटेन जैसे कुछ राष्ट्र भक्तिभाव से उसके पीछे लगे रहते हैं तो कुछ इसे बेमन से या अनमने अंदाज में स्वीकार करते हैं। शायद दुनिया के विशिष्ट आभिजात्य क्लब में बने रहने के लिए। कुछ देश अपनी आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर भी ऐसा करते हैं। पर, अमेरिका का बदलता रवैया धीरे-धीरे पिछलग्गू मुल्कों के लिए भी चिंता का सबब बन रहा है। इसकी बानगी रूस व यूक्रेन की जंग में इन देशों की भूमिका से मिलती है। यूक्रेन का साथ देने में नाटो के कुछ सदस्य देश अनिच्छापूर्वक अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। यूक्रेन को सहायता दान या अनुदान नहीं है, बल्कि बाद में यही देश यूक्रेन से इस पैसे को मय ब्याज के वसूलेंगे। यूक्रेन के नागरिक भी देश में युद्ध आपातकाल के कारण एक सक्षम और योग्य राष्ट्रपति को चुनने से वंचित हैं। अमेरिकी क्लब का दबाव उन्हें जेलेंस्की जैसे कठपुतली राष्ट्रपति को बनाए रखने पर मजबूर है। क्या पिछले वर्षों में अफगानिस्तान और इराक समेत कई राष्ट्रों की दुर्दशा के हम साक्षी नहीं हैं? यह प्रश्न सिर्फ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों का ही नहीं है। यह तमाम देशों में लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है।

पिछली शताब्दी में कई राष्ट्रों ने अपनी शासन प्रणाली में लोकतंत्र को अपनाया है। यह लोकतंत्र कामयाबी से आगे बढ़ता रहा है। भारत जैसा विराट मुल्क इसका उदाहरण है। लेकिन जिन देशों ने जम्हूरियत के साथ खिलवाड़ किया और फौजी हुकूमत अथवा अधिनायकवाद को मंजूर किया, उसके दुष्परिणाम भी उन्होंने देखे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देश इसकी उम्दा बानगी हैं। अमेरिका और भारत संसार के बड़े जम्हूरियत पसंद राष्ट्र हैं। यह दोनों पहिये लोकतंत्र की गाड़ी को खींच रहे हैं। यदि एक पहिया कमजोर हुआ तो विश्व के लोकतांत्रिक आसमान पर घने संकट के बादल छाएंगे और आसानी से उनके छंटने की आशा नहीं दिखती।

आज का इतिहास

1954 इटालियन पर्वतारोही लिनो लेसेलेली और एचीले कॉम्पानोनी हिमालय शिखर के 2 पर पहुंचने में सफल हुए।

1971 अपोलो-15 अंतरिक्ष यात्रियों ने इलेक्ट्रिक का साढ़े 6 घंटे की यात्रा की।

1972 द ट्रिब्ल्स-फ्री डेरी, एक स्वायत्त स्व-घोषित क्षेत्र हैडेरी, उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटिश सेना के संगठन मोटरमैन द्वारा समाप्त किया गया था।

1973 बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर DC-9, डेल्टा एयरलाइंस कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 89 यात्री मारे गए और एक आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गया। लेकिन अकेला जीवित रहने वाले की 6 महीने बाद मौत हो गई।

1975 द ट्रिब्यूट्स-इन बॉटेड अर्धसैनिक हमले में तीन सदस्य लोकप्रिय मियामी शोबैंड और दो उल्स्टर वालंटियर फोर्स के बंदूकधारियों को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी डाउन में मार डाला गया।

1975 द ट्रबल- एक बोटेड अर्धसैनिक हमले में, उत्तरी आयरलैंड के काउंटी डाउन में लोकप्रिय मियामी शोबैंड के तीन सदस्य और उल्स्टर वालंटियर फोर्स के बंदूकधारियों को मार गिराया गया।

1982 यूगोस्लाविया ने कीमतों पर छह महीने के लिए रोक लगा दी।

1982 अमेरिकन यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन का गठन किया गया है। वे देश जो महासंघ के सदस्य हैं, वे फ़िनलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस हैं।

1991 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने सामरिक शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किये।

1991 सोवियत स्पेशल पर्पस पुलिस यूनिट की टुकड़ियों ने लिथुआनियाई सीमा चौकियों के खिलाफ अभियान के सबसे गंभीर हमले में मेडिनिंकाई में सातवीं रैखिक सीमा शुल्क अधिकारियों को मार डाला।

2006 आंतों की सर्जरी के बाद, फिदेल कास्त्रो ने अपने भाई राउल को क्यूबा के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का अनंतिम रूप से पालन किया।

न्यायालयों में पहले ही अपने घुटने छिलवा चुका था लोकतंत्र विरोधी प्रतिबंध

लोकेन्द्र सिंह राजपूत

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। अब कर्मचारी संघ की गतिविधियों में सामान्य नागरिकों की भाँति शामिल हो सकेंगे। निःसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करनेवाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भाँति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हुए तत्कालीन सरकार ने 58 वर्ष पहले 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का विधान भी रखा गया था। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था।

इस तानाशाही एवं द्वेषपूर्ण निर्णय का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही आईना दिखाने का कार्य किया। संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवायी गईं। लेकिन संघ विरोधियों के ये सब प्रयास विफल ही रहे। निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका। अपनी 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा।

कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधि में शामिल होने पर सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया तत्कालीन सरकार का आदेश संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था। इस प्रतिबंध को 1966 के बाद से ही चुनौती मिलने लगी थी। क्योंकि संघकार्य को बाधित करने और स्वयंसेवकों को प्रताड़ित करने की जिस मंशा से सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था, उसे अंजाम देने का कार्य देशभर में शुरू किया गया। इस प्रतिबंध को हथियार बनाकर सरकारों ने देश के विभिन्न राज्यों में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की नौकरी छीनना शुरू कर दिया। सरकार की मनमानी को

स्वयंसेवकों ने न्यायालयों में चुनौती दी, जहाँ सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। मैसूर उच्च न्यायालय ने वर्ष 1966 में रंगनाथचार अग्निहोत्री की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या आरएसएस एक गैर-राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो कि गैर-हिंदुओं के प्रति किसी भी द्वेष अथवा घृणा की भावना से मुक्त है। इसी क्रम मे न्यायालय ने आगे कहा कि संघ ने भारत में लोकतान्त्रिक पद्धति को स्वीकार किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा याची को सेवा से हटाने का निर्णय गलत है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्णय सुनाया। इसी प्रकार, वर्ष 1967 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारी रामपाल को पद से हटाने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संघ कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, अतः इसकी गतिविधियों में भागीदारी करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा रामपाल को पद से इस आधार पर हटाया गया था कि वे आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं राज्य की दृष्टि में आरएसएस एक राजनैतिक संगठन है। 'भारत प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य' प्रकरण में तो 1973 में मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में भाग लेने के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। किसी अंतरस्थ हेतु जारी किया गया (इस आशय का) कोई आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता। यानी न्यायालय ने संघ की गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए लगाए गए किसी भी प्रतिबंध/आदेश को अवैध करार दिया। इसके अलावा 'मध्यप्रदेश राज्य बनाम राम शंकर रघुवंशी तथा अन्य (1983)', मामले में उच्च न्यायालय, 'श्रीमती थाद्दुमकर बनाम महाप्रबंधक टेलीकम्यूनिकेशन्स, केरल मंडल (1982)' मामले में अर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय और 'डीबी गोहल बनाम जिला न्यायाधीश, भावनगर तथा अन्य (1970)' मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिए कि संघ से जुड़े होने या उसके कार्यक्रमों में शामिल होने के आधार पर किसी कर्मचारी पर न तो कार्रवाई की जा सकती है और न ही उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले ही निशाना बनाया गया। इन मामलों से स्पष्ट है कि तत्कालीन सरकारें शुरू से ही चाहती थीं कि संघ के कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जाए। ताकि हिन्दुओं के संगठन के कार्य को रोका जा सके। परंतु, न्यायपालिका से लेकर आमजन की कसौटी पर राष्ट्रीय विचार को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल रहे। 'कृष्ण लाल बनाम मध्यभारत राज्य (1955)' में इंदौर स्थित मध्यभारत उच्च न्यायालय, 'चिंतामणि नुरगांवकर बनाम पोस्ट मास्टर जनरल, कें.मं., नागपुर (1962)' में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ, 'जयकिशन महरोत्रा बनाम महालेखाकार (1963)' में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 'केदारलाल अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य (1964)' मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय और 'मनोहर अंबोकर बनाम भारत संघ तथा अन्य (1965)' प्रकरण में दिल्ली स्थित पंजाब उच्च न्यायालय ने यही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैरकानूनी संगठन नहीं है। सरकारी कर्मचारी को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी संघ का सदस्य है तब भी उसे इस आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। स्मरण रखें कि वर्ष 1932 में अंग्रेजों ने भी सरकारी कर्मचारियों के संघ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी हुकुमत की ओर से जारी परिपत्र में आदेश दिया गया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी। कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए जिस प्रकार का प्रतिबंध कांग्रेस सरकार ने लगाया, वह औपनिवेशिक काल की अंग्रेजों की नीति को ही आगे बढ़ाने का कार्य था।

बाद के वर्षों में जब राज्यों में राष्ट्रीय विचार का पोषण करनेवाली सरकारें आईं तो उन्होंने लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकार विरोधी इस प्रतिबंध को राज्यों में समाप्त कर दिया। संघ ने इस प्रतिबंध की कभी चिंता नहीं की क्योंकि न्यायालयों में इस तुगलकी फरमान के घुटने इतने अधिक छिल गए थे कि यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। फिर भी, वर्ष 2000 में जब संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह 'रज्जू भैया' से पूछा गया कि संघ इस प्रतिबंध को लेकर क्या सोचता है? तब उन्होंने कहा था कि संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने अथवा हटाने की कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके निर्णय का अधिकार सरकारों के पास है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया। बाद में उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी प्रतिबंध को हटा लिया। यह प्रतिबंध केवल केंद्र सरकार में रह गया था, उसे भी वर्तमान केंद्र सरकार ने संघ के हस्तक्षेप के बिना, स्वतः ही समीक्षा करने के बाद हटा लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी संतुलित टिप्पणी की गई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है।

भाजपा पर कांग्रेसी संस्कृति का साया!

राजकुमार सिंह

उत्तर प्रदेश भाजपा में मचा घमासान कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति की याद दिलाता है। आजादी के बाद का कुछ समय छोड़ दें तो राज्य-दर-राज्य कांग्रेस गुटबाजी की शिकार रही। 2014 के बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक दुर्गति के दौर में भी ये दृश्य नजर आए। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता से बेदखली में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग की बड़ी भूमिका रही। छत्तीसगढ़ में भी 'भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव' कांग्रेस को ले डूबा। मध्यप्रदेश में कमलनाथ और

दिग्विजय सिंह की जोड़ी द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध छेड़ी गई जंग पहले सरकार को ले डूबी और फिर पार्टी को भी। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की चुनावी सफलता का संकेत है कि कांग्रेस आलाकमान ने गलतियों से सबक सीखा है, लेकिन अब उसी बीमारी से भाजपा ग्रस्त नजर आ रही है। अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति तथा चाल, चेहरा और चरित्र बदलने का वायदा करनेवाली भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर भी तमाम तरह के कांग्रेसियों को ही गले लगा लिया। राजनीतिक जंग में सबकुछ जायज करार देते हुए भाजपाई रणनीतिकार इसे पार्टी के विस्तार की रणनीति बताते रहे हैं, लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव में लगे झटके के बाद राज्य-दर-राज्य मुखर अंतर्कलह से लगता है कि पार्टी ने अनुशासन को तिलांजलि देकर कांग्रेस की अंतर्कलह की संस्कृति को अपना लिया है।पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीत लेने से उत्साहित भाजपा ने इस बार 370 का नारा दिया था, लेकिन सिमट गई 240 पर। खैरियत रही कि चुनाव से पहले राजग में लौट आए तेदेपा और जदयू जैसे सहयोगियों की बदौलत बहुमत का आंकड़ा मिल गया, वरना हैट्रिक का सपना चूर हो जाता। इस चुनावी सदमे की समीक्षा होनी ही चाहिए लेकिन उस प्रक्रिया में जिस तरह अंतर्कलह मुखर हो रहा है, वह कई सवाल उठाते हुए आशंकाओं को भी जन्म दे रहा है। भाजपा की सीटें तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों में घटीं, पर सबसे बड़ा झटका उसे उत्तर प्रदेश में लगा। उत्तर प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा शक्ति स्रोत भी रहा है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने दम पर बहुमत उत्तर प्रदेश की बदौलत ही पा सकी थी। 2014 में भाजपा ने 80 में से 71 सीटें जीतीं तो 2019 में 62, लेकिन इस बार सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उसे 33 पर समेट दिया। भाजपा बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें पीछे छूट गई और अकेले उत्तर प्रदेश में उसकी 29 सीटें कम हुईं। यह भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के महत्व और गंभीरता, दोनों का संकेतक है, लेकिन चुनावी समीक्षा से जिस तरह अंतर्कलह को हवा मिल रही है, उससे समाधान के बजाय संकट गहराएगा ही।

जम्मू-कश्मीर में प्रभावी रणनीति की जरूरत

सुशांत सरीन

पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कुछ तेजी आयी है, पर अभी जो हो रहा है, वह कमोबेश तीस वर्षों से होता आया है। मौजूदा समय में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी हस्तक्षेप भी स्थानीय तत्वों की तुलना में अधिक बढ़ गया है। अभी भी कुछ स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं, पर हमलों में हालिया बढ़ोतरी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ, खासकर जम्मू क्षेत्र में, के कारण हुई है। इस संख्या के बारे में अटकलें हैं।

जितनी तीव्रता से हमले हुए हैं और जितने बड़े क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं, उससे यह लगता है कि जम्मू क्षेत्र में आतंकी गुटों ने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने की वजह से हमले करना बहुत मुश्किल है। वहां छोटी-मोटी वारदातें होती हैं, जैसे किसी निहत्थे आदमी को कहीं मार दिया या गोलीबारी कर दी। यह कहने का यह मतलब नहीं है कि घाटी में बड़े हमले नहीं हो सकते, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है।

तीन दिन पहले उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा में एक हमला हुआ है। कुपवाड़ा उन क्षेत्रों में है, जो शुरू से ही आतंक-प्रभावित रहे हैं। इस हमले से पाकिस्तान, जो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहता है कि ऐसे हमलों से उसका लेना-देना नहीं है, की पोल खुल गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान जान-बूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद को काबू में करने में कामयाबी मिली है, तो उसने जम्मू की ओर रुख किया है। जम्मू क्षेत्र में आतंकियों को भागने, छुपने और नियंत्रण रेखा पार करने में आसानी होती है। जम्मू इलाके में जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर असर पड़ा है क्योंकि बहुत से सैनिकों को वहां से हटाकर चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। सुरक्षा तंत्र में ऐसी कमियों का फायदा आतंकियों ने उठाया है। इस क्षेत्र में 15-20 वर्षों से बड़ी आतंकी वारदातें नहीं हो रही थीं, तो यह मान लिया गया कि यहां पर आतंकवाद की समस्या का समाधान कर लिया गया है। अगर आतंकियों की संख्या 40-50 है और उनके सात-आठ गुट हैं, तो उन्हें खत्म करना खास मुश्किल काम

नहीं है। लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यह समस्या जटिल भी है और बड़ी भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी, इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बेहतर करना होगा और रणनीतिक समीक्षा करनी होगी। इन कामों में समय लगेगा। आतंकवाद की समस्या के समाधान में महीनों भी लग सकते हैं और शायद एक-दो साल भी लग सकते हैं। मुझे लगता है कि भारतीयों के साथ एक परेशानी यह है कि हम विजय की घोषणा करने में जल्दी में रहते हैं। इससे बचा जाना चाहिए।

अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान में यह सोच पैदा हुई कि उनके पास भारत को चुनौती देने का कोई जरिया नहीं है, तो फिर आतंकवाद का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो भारत यह समझने लगेगा कि पाकिस्तान के पास तो कोई क्षमता ही नहीं है, कश्मीर में उसका कोई औचित्य नहीं रहा और वह पाकिस्तान को पूरी तरह अनदेखा कर सकता है। पाकिस्तान ऐसी घटनाओं के जरिये यह संदेश देना चाहता है कि वह जब चाहे जम्मू-कश्मीर को अशांत कर सकता है। दूसरा पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक कलह है। वहां सेना की छवि को, खासकर पंजाब प्रांत में, बहुत नुकसान हुआ है। सेना की सोच है कि वह पाकिस्तान की जनता को फिर से अपने पीछे तभी लामबंद कर सकती है, जब भारत के साथ तनाव बढ़े। सेना के मौजूदा प्रमुख आसिम मुनीर वही व्यक्ति हैं, जो तब आइएसआइ के मुखिया थे, जब पुलवामा का हमला हुआ था।

वे इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रखते हैं। शायद उनका मानना है कि उनके पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख रहे कमर बाजवा की नीति भारत के बरक्स कमजोर रही थी, जिसके चलते भारत को ऐसा मानने का आधार मिल गया था कि अब लड़ाई में पाकिस्तान कहीं बचा ही नहीं है। तो, उनकी समझ यह है कि भले उनके पास भारत को सीधे चुनौती देने की क्षमता न हो, पर गले की हड्डी तो बन ही सकते हैं। जेनरल मुनीर सेना और अपनी छवि चमका कर अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश में भी है, जो अगले साल खत्म होने वाली है। उन्हें यह भी लगता है कि भारत में जो नयी सरकार बनी है, वह शायद वैसे ठोस फैसले न ले पाये, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में हुआ था। एक पहलू यह भी है कि पाकिस्तान यह टेस्ट करना चाहता है कि वह भारत के साथ तनाव को किस हद तक ले जा सकता है।

जहां तक राजनीतिक प्रयासों का सवाल है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने अनेक गलतियां की हैं। किसी स्थिति के दो आयाम होते हैं- आवश्यक और समुचित। अगस्त 2019 में संविधान में जो संशोधन हुए, वे कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम थे। समुचित कदम का मतलब है कि राजनीति स्तर पर वहां क्या पहल हुई। कश्मीर में पुराने ढर्रे की राजनीति में एक ओर अलगाववाद को भी शह दिया जाता था और दूसरी ओर भारत के लिए भी आवाज उठायी जाती थी। इस दोहरे मानक वाली राजनीति को बदलने की जरूरत थी ताकि कश्मीर से एक ही आवाज आये, जो भारत के लिए हो। इस मोर्चे पर विफलता रही। वहां की मुख्यधारा की पार्टियों को दूर कर दिया गया। ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए था कि अब पुराने ढर्रे की राजनीति कारगर नहीं होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हालिया चुनाव में इंजीनियर राशिद की जीत भी एक संकेत है कि सरकार वैकल्पिक राजनीति को बढ़ावा देने में असफल रही। नयी पार्टियों का भी कोई खास असर नहीं दिखता। पांच साल में ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसे उपलब्धि कहा जा सके। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल के ऊपर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहां का प्रशासन भी ऐसा नहीं है कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हों। सवाल यह नहीं है कि विकास कितना हुआ, सवाल यह है कि लोगों को लगना चाहिए कि विकास कार्य हो रहे हैं।

विपक्ष की मुस्लिमों के प्रति अंधश्रद्धा

योगेन्द्र योगी

मुस्लिम वोटों के लिए विपक्षी नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपक्षी दलों को लगना चाहिए कि हितैषी बनने का दिखावा करने मात्र से मुस्लिम वोटों को बटोरा जा सकता है। इसके बाद इन दलों में आपस में ही सच्चा हितैषी साबित करने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। वोटों की खातिर मुस्लिमों के प्रति इस अंधश्रद्धा का ही परिणाम है कि इसके प्रतिक्रियास्वरूप भाजपा ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मजबूत पकड़ बना ली, बल्कि लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में भी आ गई। हालांकि इसमें काफी हद तक केंद्र सरकार के विकास कार्य भी शामिल हैं। मुस्लिमों का हितैषी बनने का नया मामला बंगलादेश का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बंगलादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए वह पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। आश्चर्य की बात यह है कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री ममता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यह जानते हुए भी ममता ने मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसा बयान दिया। इससे पहले भी ममता बनर्जी सरेआम मुस्लिमों का पक्ष लेती रही हैं। इसके लिए बेशक कानून की मंजूरी हो या नहीं। बर्मा के रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला भी केंद्र सरकार के अधीन था। केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कि भारत में किसे शरण देनी है और किसे नहीं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर केंद्र के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए ममता ने कहा था कि सभी आम लोग आतंकवादी नहीं हैं और उन्होंने समुदाय का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई थी। ममता बनर्जी की शह पाकर कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में रैली निकाली और प्रधानमंत्री मोदी की निर्वासन योजना

का विरोध किया तथा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारत में आश्रय की मांग की। यह मुद्दा मुस्लिमों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसमें दूसरे विपक्षी दल भी कूद गए। मुस्लिमों के मामले में सभी विपक्षी दलों को लगता है कि कहीं दूसरा दल वोट बैंक का ज्यादा हिस्सा नहीं ले जाए, इसी वजह से मुद्दा चाहे राज्यों का हो या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हो, बहती गंगा में हाथ धोने से कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुस्लिम वोट की खातिर ममता किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा इमाम और मुअज्जिन को लेकर बुलाई कांफ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। विरोधी पार्टियों ने इस कांफ्रेंस के मद्देनजर ममता पर खुलकर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करने के आरोप लगा दिए। समूचे बंगाल के इमाम और मुअज्जिन इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में कोलकाता पहुंचे थे। गठबंधन की सहभागी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए ममता से मुसलमानों के समग्र विकास के लिए श्वेतपत्र जारी करने की मांग कर दी। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री ममता से सवाल पूछते हुए कहा कि ममता बनर्जी को श्वेत पत्र देकर बताना चाहिए कि वक्फ संपत्ति को बेचकर कितने प्रोमोटर करोड़पति हो गए और इनमें से कितने आपकी पार्टी के हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में ममता बनर्जी कानून को भी ठेंगा दिखाने में पीछे नहीं रहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के शासन में 2011 से बंगाल में जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाण-पत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। इसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय को इस आरक्षण का फायदा मिल रहा था। न्यायालय के इस निर्णय पर ममता बुरी तरह भड़क गईं। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने यहां तक कह डाला था कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आर.एस.एस. का व्यक्ति हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो गया... आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे हो सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, ममता सरकार ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में अभियुक्तों को बचाने के लिए पुरजोर पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? गौरतलब है कि ई.डी. अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था।

ममता बनर्जी ही नहीं, मुस्लिम वोट बैंक की खातिर अपराधी, आतंकी और देश विरोधी बयान देने वालों को गले लगाने के लिए राजनीतिज्ञ न सिर्फ आतुर रहते हैं बल्कि आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान मुस्लिम माफियाओं और अपराधियों को भरपूर संरक्षण दिया गया। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा अध्यक्ष ने खूब घडियाली आंसू बहाए थे। दरअसल भाजपा के बढ़ते प्रभाव के कारण क्षेत्रीय दलों के पास वोट बैंक बनाने के अवसर सीमित हो गए हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में ज्यादा हिस्सा बटोरने के लिए सही-गलत की विवेचना किए बगैर विपक्षी दल मुस्लिमों के समर्थन के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आते।

महाराष्ट्र के राजभवन में 'तमिलनाडु के मोदी'

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति के केंद्र में स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व विराट होकर उभरा है, इसके साथ यह भी सच है कि उनकी खास पहचान उनकी दाढ़ी है। साल 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का अपनी ओर से दावेदार बनाया था, उन्हीं दिनों एक तमिल टीवी पर चर्चा में तमिलनाडु के बीजेपी का एक चेहरा भी शामिल हुआ था। उस नेता ने अपनी पार्टी का दमदार तरीके से पक्ष रखा। उसका कार्यक्रम का ऐसा प्रभाव रहा कि उन्हें दर्शकों ने तमिलनाडु के मोदी के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के वही मोदी अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जी हां, आपने ठीक समझा, तमिलनाडु के लोग सी पी राधाकृष्णन को तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी जानते हैं। 1998 और 1999 के आम चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से लोकसभा पहुंच चुके सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारतीय जहां सीपी के नाम से जानते हैं, वहीं उत्तर भारत में अब वे राधा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी और पूजा-पाठ में श्रद्धा रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को पहली बार महत्वपूर्ण राजकीय पद साल 2023 में मिला, जब उन्हें मोदी सरकार ने झारखंड का राज्यपाल मनोनीत किया। 12 फरवरी 2023 का दिन उनके लिए खुशी और निराशा, दोनों का मौका बनकर आया। जब मोदी सरकार ने उन्हें खनिज और प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड राज्य का राज्यपाल का दायित्व मिलना मामूली बात नहीं, लेकिन 66 साल की उम्र राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। सीपी इस बात से किंचित निराश थे कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ेगा। वैसे सीपी की दिली चाहत सक्रिय राजनीति में रहते हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व को निभाना रहा है। सीपी राधाकृष्णन की बीजेपी की राजनीति में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते आम चुनावों से ठीक पहले जब तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सोंदरराजन ने इस्तीफा देकर चेन्नई से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो तेलंगाना के राज्यपाल का प्रभार सीपी को ही मिला। इतना ही नहीं, उन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल की भी जिम्मेदारी दी गई। एक साथ तीन-तीन राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी बहुत कितने लोगों को मिल पाई है? सीपी राधाकृष्णन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां कांग्रेस का बोलबाला था। उनके चाचा कोयंबटूर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रहे। सीपी बताते हैं कि पहली बार वे दिल्ली अपने चाचा के पास ही आए थे और उनके घर पर रहकर ही दिल्ली देखी थी। चार मई 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में जन्मे राधाकृष्णन कांग्रेसी पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद कांग्रेस की बजाय समाजवादी युवा आंदोलन से जुड़े। जनता पार्टी के दौर में तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष रहे इरा सेझियन से सीपी राधाकृष्णन का गहरा नाता रहा। 1983 की जनवरी में तत्कालीन जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भारत यात्रा शुरू की थी। तब तमिलनाडु में उनकी यात्रा से जुड़े आयोजनों की व्यवस्था में 28 वर्षीय युवा सीपी ने अहम भूमिका निभाई। तब चंद्रशेखर की उन पर नजर पड़ी। बाद में रोजगार के लिए होजरी के कारोबार से जुड़े सीपी का नाता शरद यादव से भी रहा। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के दौरान शरद यादव कपड़ा राज्यमंत्री थे। उन दिनों उन्होंने कोयंबटूर का दौरा किया था, तब शरद यादव के लिए सीपी ने भोज दिया था। बाद के दिनों में सीपी भाजपा से जुड़ गए और देखते ही देखते भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बना दिए गए। उनकी अध्यक्षता में ही बीजेपी ने 1998 और 1999 का चुनाव लड़ा और चार सीटों पर जीत हासिल की।

बारिश के मौसम में मकान को खूबसूरत रखना बड़ा कठिन है। कहीं कोई सामान भीग रहा है तो कहीं फर्नीचर खराब हो रहा है। अगर इन सबसे बचना है तो थोड़ी सी सावधानियां रखकर इनसे बचा जा सकता है।

बरसात में बनाएं घर को खूबसूरत

काफी इंतजार के बाद अब मानसून का मौसम आ गया है। इस मौसम में घर की खूबसूरती बनाए रखने में सबसे अधिक परेशानी आती है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि घर में ह्यूमिडिटी को कम से कम किया जा सके। दूसरे इस बात के चलते घर के इंटीरियल पर कोई खास असर न पड़े। यदि आप बारिश के मौसम का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते है तो इसके लिए आपको घर में कुछ बदलाव करना जरूरी है। आइए जाने ये बदलाव कैसे करें।

हरी-भरी गली

इंडोर प्लांट्स के लिए मानसून सबसे अच्छा मौसम होता है। इस वक्त धूप कम होती है, इसलिए अपने सभी आउटडोर प्लांट्स को निकाल कर बारिश में रख सकते है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट्स हरे-भरे और आकर्षक लगेंगे।

फ्रेश वार्डरोब

मानसून में अच्छी धूप न मिल पाने के कारण कपड़े गीले रह जाते हैं। इस कारण से वार्डरोब में गीले कपड़ों की बदबू आने लगती है। आडोनिल के एयरफ्रेशनेस पैक्स, नैपथलीन, बाल्स, कपूर, नीम की पतियां और लांस का उपयोग इस स्मेल, बैक्टीरिया और फंगस से बचा जा सकता है।

कारपेट एवं रग्स

मानसून में सबसे ज्यादा परेशानी अपने कारपेट्स और रग्स को संभालने में होती है। कारपेट और रग्स को ड्राई क्लीन कराने के बाद इन्हें प्लास्टिक बैग्स में संभाल कर रख देना चाहिए।

लेदर प्रॉडक्ट्स

नमी के कारण लेदर प्राडक्ट्स, शूज, हैंड बैग्स, लैपटॉप बैग्स, सीट्स और सोफा सेट में फंगस से बचाने के लिए लेदर क्लीनर्स से इन्हें साफ किया जा सकता है।

कर्टन के तरीके

मानसून में भी फैब्रिक्स की लेयर्स नहीं होनी चाहिए। इससे ह्यूमिडिटी बढ़ती हैं। परदो मे हलके फैब्रिक्स का उपयोग करें। इसके लिए रेग्यूलर बेसिस पर शिफान, नेट और स्पेशल ओकेजंस पर टस्सर सिल्क फैब्रिक में कर्टन चुनें।

चांदी के सामान

चांदी को सर्वाधिक नुकसान आक्सिडाइजेशन से होता है, जो बारिश के मौसम में होता है। नमी और हवा में मौजूद आक्सीजन दोनों मिलकर चांदी को काला बना देते है। इन्हें बचाने के लिए ज्यूलरी और बर्तनों को काटन फैब्रिक और पेपर में लपेट कर रख सकते हैं।

टच वुड

मानसून का असर वुडेन फ्लोरिंग पर भी देखने को मिलता है। एक तो ह्यूमिडिटी और दूसरे गीले कारपेट व मेट, दोनों मिलकर वुडेन फ्लोरिंग, किचन वुड शेल्फ को जल्दी खराब कर सकते हैं। अधिक नमी होने से लकड़ी भीगकर टूटने-मुड़ने लगती है। इसके लिए मानसून से पहले इन्हें वैक्स कोटिंग करा लेना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक गैजेट्स

मानसून के मौसम में कैमरा लैंस, कम्प्यूटर मॉनिटर, एलसीडी टेलीविजन में फंगस लग जाती है। कैमरा केस में नमी को कंट्रोल करने के लिए उसमें सिलिकन बेग रखे जा सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर और एलसीडी टेलीविजन के आसपास नमी पैदा करने वाली चीजों जैसे कूलर को दूर रखना चाहिए। क्लीनिंग के वैक्यूम क्लीनर का उपयोग बेहतर विकल्प हैं।

किराए का घर और साज-सज्जा

कई लोग जो किराये के घर में रहते हैं, उनके लिए घर की सजावट को लेकर कई समस्याएं होती हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए, जिनका तबादला बार-बार होता रहता है। उनके लिए फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए, जिससे जगह बदलने पर मुश्किल न हो। जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, वे अपना घर कैसे सजाएं? हम यहां किराए के घर में रहने वालों के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं।

- फर्नीचर हल्के बनवाएं। सोफे की जगह केन, रॉट आयरन-वुड कॉम्बीनेशन, मेकेनाइज्ड फर्नीचर या गद्दों का इस्तेमाल करें। ये फर्नीचर जल्दी नहीं टूटते हैं।
- अगर आप सोफा बनवाना चाहती हैं, तो गद्दी अलग रखवाएं।
- स्थानांतरण में इस्तेमाल होने वाले बड़े बॉक्स के ऊपर गद्दा डाल कर सेटी या मेज का काम ले सकती हैं।
- दीवारों पर न्यूट्रल रंग करवाएं, जो हर फर्नीचर के साथ अच्छा लगेगा।
- रोशनी के लिए टेबल लैंप या स्टैंडिंग लैंप लगवाएं। स्थायी व्यवस्था ना करें।
- घर में परदों का बहुत महत्व होता है। किराए के घर में अनेक बदरंगी दीवारों, अलमारियों आदि को ढंकने के लिए खूबसूरत परदे लगाएं।
- परदे खूबसूरत, शालीन व ऐसे रंगों के लें, जो आप घर बदलने पर भी इस्तेमाल कर सकें।
- फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बहुउपयोगी होती है। इसे आप किसी भी कमरे में रख सकती हैं। यह जगह भी कम घेरेगी।
- घर के अंदर सिल्क प्लांट का इस्तेमाल करें। ये नकली प्लांट बेहद खूबसूरत, टिकाऊ और इस्तेमाल में आसान होते हैं।
- बेड व सेटी में स्टोरेज बनवाएं, ताकि सामान ले जाते समय दिक्कत न हो।
- किराए के घर में महंगे, भारी-भरकम फर्नीचर रखने का मोह छोड़ें।
- अगर कमरे बड़े हैं, तो दो या तीन सिटिंग अरेंजमेंट कर सकती हैं।
- घर जमाते समय समान की लिस्ट बना लें कि आपके पास क्या-क्या है और कौन-सी चीज आपने अटारी में रखी है।

साफ-सफाई के बेहतर टिप्स

बरसात के मौसम घर में अनेक वस्तुओ की साफ-सफाई करनी पड़ती है। इसके लिए ये टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे।

- अगर कपड़े की झाड़न पर गर्द कुछ ज्यादा हो गई हो और सफाई में दिक्कत आ रही हो तो हाथों को थोड़ा गीला कर कपड़े पर फिरा दें फिर जल्दी से उसे ब्रश से झाड़ डाले नमी की वजह से कपड़े की पूरी गर्द आसानी से उतर जाएगी।
- रजाई-तकिए के कवर धोकर आखिरी बार खंगालते समय पानी में थोड़ा सिरका मिला दीजिए। अब देखिए चमत्कार, सिरके के अम्ल से कपड़ों से साबुन का क्षार फौरन उतर जाएगा। इससे कवर का कपड़ा भी मुलायम हो जाएगा।
- रजाई के कवर को आसानी से चढ़ाने के लिए धोने के बाद उलटा सुखा दें। उलटे कवर के अंदर रजाई के दोनों कोने डालकर गोल-गोल लपेटते जाएं। जब रजाई पूरी गोल हो जाए तो नीचे वाला सिरा खींच लें। रजाई के दोनों कोनों को पकड़ लें और साथ-साथ उठाकर दो तीन बार झटक दें। उलटा हुआ कवर सीधा होकर रजाई पर आसानी से सीधा होकर चढ़ जाएगा।
- आपके यहां डस्टबिन मेटल का है तो आप उसके अंदर से आने वाली बदबू से जरूर परेशान हो सकते हैं। इसका आसान सा इलाज है। मेटल के कूड़ेदान की बदबू खत्म करने के लिए उसमें पुराने अखबार डाल कर आग लगा दें। आग समस्या का समाधान कर देगी।
- टॉयलेट में बहुत बदबू आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए इसे हटाने के लिए माचिस की तीली जला देना भर काफी है।
- आपके घर भी यदि खारा पानी आता है और आपके बाथरूम में हर चीज इसकी वजह से सफेद हो गई है तो आप इन सभी को पैराफिन से साफ कर सकते है। इससे बाथरूम का फर्श, बाथ टब और टोंटियां और वाशबेसिन साफ हो जाते हैं। इन पर जमे साबुन की चिकनाई और भी मैल साफ हो जाता है और पैराफिन से इनकी चमक भी लौट आती है।
- बाथरूम में पानी की टपकने या कहीं-कहीं पानी जमने से बने भूरे धब्बों को नमक और सिरके की बराबर मात्र के मिश्रण से दूर किया जा सकता है। टब, बाल्टी या पानी भरने के दूसरे बर्तन में भी यदि सफेदी जमा हो गई हो तो इसी विधि को उन पर भी आजमा सकते हैं।

दीवानगी ड्रेप्ड ड्रेसेज की

आजकल लड़कियां बॉलीवुड और हॉलीवुड की नकल तेजी से कर रही हैं। हॉलीवुड में चर्चित ड्रेप्ड ड्रेसेज का चलन इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहा है। किसी खास पार्टी में इस तरह की ड्रेस पहने कोई न कोई दिख ही जाएगा। इन दिनों लड़कियों को ड्रेप्ड ड्रेस खूब भा रहा है। गाउन से मिलती-जुलती ड्रेप्ड ड्रेस बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है।

क्या है ड्रेप्ड ड्रेस

जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि यह कोई ऐसा ड्रेस है जो लपेटा हुआ होता है। यदि आप इस ड्रेस को देखें तो ऐसा लगेगा कि किसी ने टॉवेल या बेडशीट लपेट लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक पूरा का पूरा ड्रेस है। अपने देश मे इसका चलन अभी शुरुआती दौर मे है, लेकिन विदेशो मे यह खूब पसंद किया जा रहा है। रिएलिटी शो बिग बॉस मे हॉलीवुड एक्टर्स पामेला एंडरसन ने इस ड्रेस को पहन कर लोगों को ड्रेप्ड ड्रेस से रूबरू कराया था। अधिकांश लोग तो समझ ही नहीं पाए थे कि टॉवेल जैसी दिखने वाली यह ड्रेस आखिर मे है क्या ? क्या पॉमेला ने कोई कपड़ा लपेटा है या यह कोई खास ड्रेस है। फैशन डिजाइनर मानते है कि ड्रेप्ड ड्रेस फिटेड हो या लूज, अगर इसे अच्छे से कैरी करेंगी, तो वह खूब फबेगी। ड्रेप्ड ड्रेसेस को अभी तक बड़े महानगरो में ही पार्टियों में पहने देखा गया है।

स्टाइल व पैटर्न

गाउन जैसा दिखने वाला ड्रेप्ड ड्रेस फैशन में लेटेस्ट ट्रेंड है। इस ड्रेस में सिलुएट्स व नॉट्स पैटर्न को खूब यूज किया जाता है। ड्रेप्ड ड्रेस को लूज ड्रेस माना जाता है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल के कारण पतली लड़कियों को भी खूब पसंद आता है। कभी-कभार पहने जाने वाला यह ड्रेस काफी बोल्ड व सेक्सी लुक देती है।

अलग-अलग है वैरायटी

अगर ड्रेप्ड ड्रेस की बात करे, तो यह कई वैरायटी में उपलब्ध है। आप इसे शॉर्ट, लॉन्ग, फिटेड व लूज पैटर्न में डिजाइन करवा सकती है। वैसे, यह इटैलियन ड्रेस है, जो काफी हद तक जंप सूट से मिलती- जुलती है। इस ड्रेस की खूबी है कि इसे 20 से लेकर 40 साल तक की महिलाएं बड़ी आसानी से कैरी कर सकती हैं।

सिलेब्रिटीज की है खास पसंद

वैसे तो ड्रेप्ड ड्रेस हॉलीवुड एक्ट्रेस की पहली पसंद है, लेकिन अब यह इंडिया में भी पॉपुलर होने लगी है। यह ड्रेस अभी बॉलीवुड तक ही सीमित है। फैशन डिजाइनर मानते भी हैं कि यह बॉलीवुड एक्ट्रेस को खास पसंद आ रहा है। यह एलिगेंट ड्रेस है और इंडियन वुमन की फिगर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनम कपूर, कंगना राणावत, रानी मुखर्जी को ड्रेप्ड ड्रेस बहुत पसंद है और इनकी वजह से ही आम लड़कियों और महिलाएं भी इस ड्रेस की ओर अट्रेक्ट हो रही हैं।

बेस्ट फैब्रिक

अगर आप ड्रेप्ड ड्रेस डिजाइन करवा रही हैं, तो इसके लिए जरूरी है बेस्ट फैब्रिक का चुनाव। चूंकि ड्रेप्ड ड्रेस में सिलुएट्स व नॉट्स खूब यूज की जाती हैं, ऐसे में लाइट कलर के फैब्रिक का चुनाव करना चाहिए। लाइट फैब्रिक में जॉर्जेट, साटन, जरदोजी, क्रेप, लिनन व जॉर्जेट का चुनाव बेहतर रहता है। यदि आप इंडो-वेस्टर्न लुक चाहती हैं तो उसके लिए भी ड्रेप्ड ड्रेस परफेक्ट है।

परफेक्ट कलर

ड्रेप्ड ड्रेस के लिए ब्राइट कलर चुनें। दरअसल, यह ड्रेस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऐसे में ब्लैक, रेड, ग्रे व क्रीम कलर ट्राई कर सकती हैं। वैसे, अम्बर प्रिंट्स में भी ड्रेप्ड ड्रेस खूब पसंद की जा रही है। इसे आप दो से तीन कलर में डिजाइन करवा सकती हैं। वैसे तो ड्रेप्ड ड्रेस प्लेन फैब्रिक में ही ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन आप इसे शादी व पार्टी के पर्पज से चाहती हैं तो इसमें स्वरोस्की, नग, लेस व सितारा वर्क करवा सकती हैं।

क्या हुआ इन क्या हुआ आउट

कलरफुल बीड्स

इन दिनों कलरफुल बीड्स का फैशन काफी इन है। खासतौर पर वाइट ड्रेस के साथ इसे खूब कैरी किया जा रहा है। चाहे आप शर्ट पहनें या सूट, बीड्स के साथ कैरी करने के लिए इसे प्लेन होना चाहिए।

सिट्रस शेड्स

आजकल सिट्र्स शेड्स बेहद डिमांड में हैं। इनमें कुर्तियां, फ्लो वाली ड्रेसेज, चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट्स, ट्यूनिक्स और साड़ियों जैसी तमाम ड्रेसेज शामिल हैं।

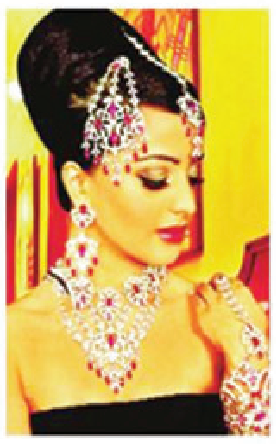

प्लेन जूलरी

इन दिनों प्लेन जूलरी बिल्कुल पसंद नहीं की जा रही है। इसकी जगह थीम पर बेस कॉकटेल जूलरी हॉट बनी हुई है, जो विक्टोरियन व मुगलकाल से इंस्पायर्ड है।

टाइट फिटेड जींस

टाइट फिटेड जींस इस सीजन में फैशन से बाहर हो गई है। हालांकि लेगिंग्स में टाइट लेगिंग्स अभी भी हॉट बनी हुई हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री ने भूस्खलन के बाद केरल के सीएम से की बात

नईदिल्ली। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्पाइड के बाद मलबे में कई लोग फंस गए है। लोगों को बचाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जान गंवाने वालों के लिए दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात भी की है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि केंद्र से हर संभव मदद राज्य को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। केरल के पहाड़ी इलाके वायनाड में मंगलवार की सुबह भूस्खलन हो गया है। इस हादसे में सूत्रों के मुताबिक तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है।

राहुल के केरल में प्रभावित जिले का दौरा की संभावना

नईदिल्ली। विपक्ष के नेता और वायनाड से पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में बचाव प्रयासों के संबंध में मंगलवार (30 जुलाई) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास कई पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के हुए भारी भूस्खलन में तीन बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। रक्षा पीआरओ के अनुसार, केरल राज्य प्रशासन ने वायनाड जिले के चूरलमाला में हुए भीषण भूस्खलन के जवाब में 122 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) मद्रास की बचाव टुकड़ियों की मांग की है। चल रहे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए एक चिकित्सा अधिकारी, दो जेसीओ और 40 सैनिकों के साथ सेकंड-इन-कमांड के तहत एक टीम तैनात की गई है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद के वायनाड जाने की उम्मीद है, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय नेताओं को मदद करने का निर्देश दिया है।

यूपी विधानसभा में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया और राज्य में अपराध की घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पार्टी को उसके पूर्व प्रमुख की टिप्पणी की भी याद दिलाई जिन्होंने बलात्कार के मामलों में आरोपी लड़कों को फांसी नहीं देने की वकालत की थी। महिला सुरक्षा से निपटने के लिए उठाए गए सरकार के कदमों पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा कि यह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने एंटी-रोमियो स्क्वॉड का गठन किया था। योगी ने कहा कि महिला और बाल अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ-साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि 2020 से हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में हम लोगों ने करीब डेढ़ लाख पुलिस कर्मी की भर्ती की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक को जमानत दी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक के वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने उल्लेख किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम मेडिकल जमानत को स्थायी बनाया जा सकता है। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े एक मामले के सिलसिले में फरवरी 2022 में मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक ने अपनी पुरानी किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से राहत मांगी और योग्यता के आधार पर जमानत का भी अनुरोध किया।

झारखंड ट्रेन दुर्घटनाः विपक्ष ने रेल मंत्री पर साधा निशाना

नईदिल्ली। झारखंड में नवीनतम ट्रेन दुर्घटना के बाद विपक्षी दलों ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रेल सुरक्षा के मामले में सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. उनके पास रिकॉर्ड संख्या में पेपर लीक और अब रेलवे दुर्घटनाएं थीं। यह सरकार सिर्फ बड़े-बड़े दावे करती है. लोगों की जान जा रही है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से कई रेल दुर्घटनाओं के बाद जवाबदेही तय करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने को कहा। पूर्व रेल मंत्री बनर्जी ने ट्वीट किया, मैं गंभीरता से पूछती हूंः क्या यह शासन है?

सीआईआई के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी

बीते दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में विकसित भारत की यात्राः केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद का सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की ओर से आयोजित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। मैं सीआईआई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप बहुत चिंता कर रहे थे। हर चर्चा के केंद्र के विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। आज भारत किस ऊचाई पर है। आज भारत 8 प्रतिशत की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, जर्नी टुवार्ड विकसित भारत। यह बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट का नहीं है यह बदलाव कॉन्फिडेंस का है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। पीएम ने कहा, मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की पहचान बन गई है चुनाव से पहले जो बातें करते हैं चुनाव के बाद भुला देते हैं। मैं वैसा नहीं हूं। इसलिए मैं याद दिला देता हूं मैंने कहा था मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। 2014 में जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया तब सबसे बड़ा प्रश्न यही था इकोनॉमी को कैसे वापस पटरी पर लाएं। 2014 से पहले ही फ्रेजाइल फाइव वाली स्थिति और लाखों करोड़ों के घोटाले के बारे में यहां हर कोई पता है। इकोनॉमी की क्या स्थिति थी इसकी बारीकियां सरकार ने श्वेत पत्र जारी के बताई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

पीएम ने कहा कि आप जैसे संगठन (सीआईआई) उस पर जरूरत के अनुसार अध्ययन करें उस पर डिबेट करें कि हम कहां खड़े थे और कैसी बीमारियों की शिकार हो गए थे?

पीएम ने दावा किया कि हम भारत को उस महासंकट से निकाल कर इस ऊंचाई पर लाए हैं। बजट 16 लाख से 48 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कैपेक्स जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपेक्स के लिए 90 हजार करोड़ था, इस साल सरकार चलाने के बाद 2014 में यह बजट 2 लाख करोड़ रुपये था। आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना की रफ्तार से बढ़ा है। बात सिर्फ बजट बढ़ाने की नहीं है बात गुड गवर्नेंस की है। पहले बजट की घोषणाएं भी जमीन पर नहीं उतार पाते थे। ये घोषणा करके हेडलाइन लेते थे पर काम नहीं होता था। योजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर भी पहले की सरकारों का कोई जोर नहीं था। हमने दस वर्षों में इस स्थिति को बदला है।

ऐसी अनिश्चितता के समय में भी विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के रोल मॉडल है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत की भागीदारी 16त्न हो गई है। ऐसा अनेकों के संकट के बाद हुआ है। पैंडेमिक, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ऐसा हुआ है। हमने हर संकट का मुकाबला किया है। हर चुनौती का समाधान किया है। अगर ये संकट नहीं आते तो भारत आज जहां पहुंचा है उससे भी ऊंचाई पर होता। आज देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है। बीते दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। हमने कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया युवाओं की मदद कर रही है। मुद्रा योजना की मदद से आठ करोड़ से ज्यादा साथियों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, लोगों युवाओं को इनमें काम मिला है। बजट में हुई पीएम पैकेज की घोषणा से चार करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार जिस तेज और स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, आप सब उसके गवाह हैं। यह अभूतपूर्व है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह बहुत अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत जैसी विकास दर होना अलग बात है। ऐसी स्थिति में भारत के मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होना भी बेहद अहम बात है। भारत इस स्थिति में भी बढ़ी विकास दर और कम महंगाई वाला देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है।

लोकसभा में राहुल गांधी मे उठाया वायनाड में भूस्खलन का मुद्दा

■ **प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की अपील की**

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड के विनाशकारी भूस्खलन का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह-सुबह, वायनाड कई विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आ गया। 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मुंडक्कई गांव का संपर्क टूट गया है और त्रासदी के पैमाने के कारण जानमाल की विनाशकारी हानि और व्यापक क्षति का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं केंद्र सरकार से बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता देने, मृत लोगों को मुआवजा तुरंत जारी करने का अनुरोध करता हूं - यदि मुआवजा बढ़ाया भी जा सकता है - महत्वपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहाल करें, जल्द से जल्द राहत स्थापित करें और एक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का रोडमैप तैयार करें। वायनाड से पूर्व सांसद ने कहा क

जब मैं बोल रहा हूं, तब भी वायनाड और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।

उन्होंने कहा कि भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों के मानचित्रण और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को संबोधित करने के लिए शमन उपाय और एक कार्य योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है। भूस्खलन की घटनाएं मंगलवार तड़के हुईं जिससे अपने घरों में सो रहे लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। लोग फोन पर मदद की गुहार लगा रहे हैं और बचावकर्मी मलबे से लोगों का निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूस्खलन की घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को संकट से निपटने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''वायनाड में कुछ जगहों पर भूस्खलन की खबर से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है और जो घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान जारी है।'' मोदी ने लिखा, ''केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की और वहां उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।'' मंगलवार तड़के हुए भूस्खलन ने तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं और कई पेड़ उखड़ गए हैं।

एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाना चाहिए : अखिलेश

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र का पहला दिन 22 जुलाई को संसद में शुरू हुआ। इस सत्र में 16 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को इसका समापन होने की संभावना है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास पहलों के बारे में सत्तापक्ष से सवाल पूछे। एफडीआई के मामले में, यादव ने पूछा कि क्या यूपी को देश में प्राप्त कुल एफडीआई का 1% से अधिक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यादव ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए धन आवंटित न करने की शिकायत भी की। कन्नौज के सांसद ने हाल ही में उद्घाटन किए गए चार लेन वाले एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है और उसे वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाना चाहिए।

हाल ही में हुए आम चुनावों के नतीजों पर बात करते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देश दस साल पहले की स्थिति में होता तो क्या सत्ताधारी दल को भी वही नतीजे मिलते? यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर भी कम हुआ है। राजकोष से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और देश में दूरसंचार विनिर्माण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यादव ने कहा कि विनिर्माण के लिए समाजवादी पार्टी की औद्योगिक नीतियों ने प्रावधान किया था, न कि मौजूदा सरकार की मेक इन इंडिया नीतियों ने। लोकसभा में कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आज हर परिवार बच्चे की शिक्षा और बुजुर्गों की दवा की चुनौतियों से परिचित है। यादव ने कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने और युवाओं तथा गांवों को राहत पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी सांसद ने राजकोष द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने वाले भाषणों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भूख सूचकांक में भारत कहां खड़ा है?

खेल
प्रमुख समाचार

मनु भाकर एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय

पेरिस। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में सरबजीत सिंह के साथ ब्रॉन्ड मेडल जीता। एक ही ओलंपिक के दौरान एयर पिस्टल स्पर्धा में दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। 124 सालों के ओलंपिक इतिहास में पहली बार ये कारनामा हुआ है।

रविवार को मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। मंगलवार को सरबजोत सिंह के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया के ली वोनहो और ओह ये जिन का सामना किया। भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर के साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया कोरियाई पर जीत हासिल की।

मनु भाकर से पहले सिर्फ दो भारतीय एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दो पदक जीत पाए थे। पहलवान सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में पदक अर्जित किए थे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह उपलब्धि न केवल मनु भाकर की प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि भविष्य के भारतीय एथलीटों के लिए प्रेरित भी करती है। उनकी सफलता से देश भर के कई युवा खेल प्रेमियों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की उपलब्धियों ने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें देश भर के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक आदर्श बना दिया है। मनु भाकर के असाधारण प्रदर्शन की बदौलत पेरिस ओलंपिक भारत के लिए एक यादगार आयोजन रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 81,455 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में मिले-जुले रुख की वजह से मंगलवार 30 जुलाई 2024 को घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में बंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 99.56 अंक या 0.12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 81,455.40 पर बंद हुआ। इसके साथ ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.20 अंक या 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 24,857.30 अंक के स्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 67 अंक चढ़कर 81,423.53 अंक पर खुला था। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी ने भी मामूली 25 अंकों की बढ़त के साथ 24,861.35 अंक के स्तर पर अपने कामकाज की शुरुआत की थी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों में से 16 लाभ में रहे, जबकि 14 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे।

योगी सरकार ने 12 हजार 909 करोड़ का बजट पेश किया

लखनऊ। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12 हजार 909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6 प्रतिशत है। बजट में सर्वाधिक 7518 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसी तरह ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग की बसों के लिए 1000 करोड़ रुपये, अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये व रोजगार मिशन समिति के गठन के लिए 49.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं व बच्चों पर होने वाले यौन उत्पीड़न पर आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर जवाब देते हुए कहा कि इन मामलों में आरोपियों को सजा देने में यूपी देश में तीसरे स्थान पर है।

एकम्स ड्रग्स के आईपीओ का हो गया आगाज

नईदिल्ली। दवा निर्माता कंपनी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार 30 जुलाई 2024 का आगाज हो गया। इसका सब्सक्रिप्शन 2 अगस्त 2024 को बंद हो जाएगा। कंपनी ने आईपीओ इश्यू का प्राइस बैंड 646-679 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 50 फंडों को 679 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1.22 करोड़ शेयर आवंटित करने का फैसला किया है। इससे पहले एकम्स ड्रग्स ने एंकर निवेशकों से करीब 829 करोड़ रुपये जुटा लिये हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल की ओर से जारी किए गए 1,856.74 करोड़ रुपये के आईपीओ में 680 करोड़ रुपये का नया इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 1,176.74 करोड़ रुपये मूल्य के 1.73 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। प्रमोटर संजीव और संदीप जैन 15.12-15.12 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे।

सोना 950 रुपये सस्ता, एक दिन में औंधेमुंह गिरी चांदी

नईदिल्ली। सोना-चांदी के गहने खरीदने और इन दोनों बहुमूल्य धातुओं में निवेश करने वालों के लिए बेहतरीन खबर है और वह यह कि देश के सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आभूषण विक्रेताओं की डिमांड में आई कमी की वजह से दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना की कीमत में करीब 950 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ गई। वहीं, चांदी की कीमत में 4,500 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 950 रुपये की गिरावट के साथ 71,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले सप्ताह शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 99.9% शुद्धता वाला सोना 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सुधार पर दीर्घकालिक नजरिये की आवश्यकता

वी एस कृष्णन

भारत में बजट को लेकर इतनी उत्सुकता और उम्मीदें क्यों होती हैं? सामान्यतया तो दुनिया के अन्य देशों की तरह इसे भी सालाना लेखा कवायद ही होना चाहिए। परंतु भारत में यह अलग इसलिए है कि 1990 के दशक के सुधार के दौरान बजट न केवल व्यापक नीतिगत सुधार की घोषणा का माध्यम बना था बल्कि उसमें ही मध्यम से लंबी अवधि की प्राथमिकताओं का ब्योरा भी दिया गया था।

इस बजट में नीतियों से अधिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। यह बजट रोजगार को लेकर खासकर युवा बेरोजगारी को लेकर सरकार की चिंताओं को जाहिर करता है। सरकार ने जो प्राथमिकताएं सामने रखी हैं वे कई तरह से इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना चाहती हैं। संतोषजनक बात यह थी किस सरकार राजकोषीय विवेक को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर टिकी रही और चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.9 फीसदी पर लाने का लक्ष्य तय किया।

अंतरिम बजट में इसके 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। यह वादा भी किया गया कि अगले वर्ष इसे 4.5 फीसदी तक लाया जाएगा। कराधान के मोर्चे पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों करों की प्रक्रिया को सहज बनाने तथा योजनाओं और रियायतों की बहुलता को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही गई है। प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में कर विवादों में कमी लाना शामिल है।

इस प्रयास में, अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क और सेवा करों से संबंधित विरासती कर मामलों में अपील दायर करने की मूल्य

सीमा बढ़ा दी गई है। करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं के डिजिटलीकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है ताकि कर भुगतान के अनुभव को कम तनावपूर्ण बनाया जा सके। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से बजट में इससे संबंधित नीतिगत घोषणाएं नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इनका निर्णय केंद्र और राज्यों की संयुक्त जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है।

वित्त मंत्री ने यह अवश्य कहा कि आगे चलकर दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और प्रक्रियाओं को सहज बनाया जाएगा ताकि कारोबारी सुगमता में इजाफा किया जा सके। सीमा शुल्क के मोर्चे पर कुछ विशिष्ट प्रस्ताव अवश्य दिए गए जहां सरकार ने एक बार फिर 18 प्रतिशत की औसत सीमा शुल्क दर को कम करके 10 फीसदी से कम करने का अवसर गंवा दिया। बजट में एक तीन स्तरीय शुल्क ढांचा पेश किया जा सकता था जहां न्यूनतम दर कच्चे माल और घटकों पर होती, उससे कुछ ऊंची दर मध्यवर्ती वस्तुओं पर और सबसे ऊंची दर तैयार वस्तुओं पर लागू होती। यदि ऐसा किया जाता तो इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे की दिक्कत भी दूर हो जाती। इसके बजाय सरकार ने क्षेत्रवार रुख अपनाने का तय किया। उसने ऐसे कई उद्योगों के कच्चे माल और घटकों बुनियादी सीमा शुल्क दर कम कर दी जिन्होंने निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें समुद्री निर्यात, सोने के आभूषण, प्लैटिनम (सोने और प्लैटिनम के आभूषणों पर लगने वाले सीमा शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है), मोबाइल फोन और चार्जर तथा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे शामिल हैं। बजट में सोलर सेल और पैनल के निर्माण में काम आने वाले पूंजीगत उपकरणों पर आयात शुल्क में भारी कमी की गई। इसके अलावा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले महत्त्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भी शुल्क कम किया गया है। श्रम के गहन इस्तेमाल वाले क्षेत्रों मसलन चमड़ा और वस्त्र आदि में भी चुनिंदा कच्चे माल पर राहत प्रदान की गई है। वस्त्र क्षेत्र में ड्यूटी इनवर्जन (जहां कच्चे माल पर अंतिम उत्पाद से अधिक कर लगता है) की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने मेथिलीन डाइफिनाइल डिसोसाइनेट (एमडीआई) जैसे कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में कमी कर दी है। उसे स्पॉन्डेक्स यार्न (सिंथेटिक लचीला धागा) बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

विकास की गति को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकताः डेका

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त राज्यपाल रामेन डेका रायपुर पहुंच चुके है। आज राज्यपाल डेका के स्वागत के लिए नवीन स्टेट हैंगर में भव्य तैयारियां की गई थीं। स्वागत समारोह में राउत नाचा, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य और अन्य आदिवासी नृत्यों के माध्यम से राज्यपाल का स्वागत किया गया।

इस भव्य स्वागत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम, लक्ष्मी रजवाड़े, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, और टंकराम वर्मा समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक संदीप साहू और रायपुर महापौर एजाज भी शामिल हुए।

राज्यपाल रामेन डेका ने अपने स्वागत समारोह के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करें और विकास की गति को तेज करें। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निरंतर काम करूंगा और राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है और विकास की राह पर अग्रसर है। हमारा काम केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाए रखना और विकास की गति को तेज करना है। छत्तीसगढ़ खनिज और संस्कृति के मामले में संपन्न है और असम और छत्तीसगढ़ के बीच संबंधों को भी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। जब राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब भाजपा का सदस्य नहीं हूँ। मैंने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब एक संवैधानिक पद पर कार्यरत रहूंगा। इसलिए, मुझे संविधान और सरकारी नियमों का पालन करना और उनका मार्गदर्शन करना होगा। लंबित आरक्षण मामलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। वर्तमान में विकास हमारी मुख्य प्राथमिकता होगी।

दसवें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल डेका प्रदेश के दसवें राज्यपाल के रूप में बुधवार 31 जुलाई को सवा दस बजे राजभवन के दरबार हाल में शपथ लेंगे। उन्हें यह शपथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा शपथ दिलाएंगे।

4 वर्ष पूर्व अचानक 68 प्रतिशत बढ़ाई गई छूट से हुआ था अरबों का गड़बड़झाला

अब भी उच्चदाब स्टील उद्योगों को छूट 4 वर्ष पूर्व से 2 प्रतिशत अधिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उच्चदाब स्टील उद्योगों को 4 वर्ष पहले अचानक खपत आधारित ऊर्जा प्रभार में दी जाने वाली छूट 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई थी, जिससे इन उद्योगों को एकदम से 68 प्रतिशत का लाभ मिलने लगा था। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से अचानक बढ़ाई गई छूट को ही न्यायोचित रूप से कम किया गया है। इससे उच्चदाब स्टील उद्योगों को मिलने वाला अतिरिक्त फायदा कम हो गया है जिसको लेकर वे गैर-वाजिब दबाव बना रहे हैं।

पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था. जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था। इस तरह विगत माह छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई तार्किक कार्यवाही के बावजूद लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में जो अधिकतम छूट 8 प्रतिशत मिल रही थी उसकी तुलना में भी 2 प्रतिशत अधिक छूट इन उद्योगों को अभी मिल रही है जिससे किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता। 4 वर्ष पूर्व छूट की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के कारण इन उद्योगों को मिलने वाली औसतन वार्षिक छूट लगभग 300 करोड़ रूपये से बढ़कर लगभग 1100 करोड़ रूपये हो गई थी। इस तरह, इन उद्योगों को लगभग 750 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त लाभ दिया गया था। इस राशि की बंदरबाट में किसको क्या लाभ हुआ होगा, इस विषय में संबंधित क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चा चल रही है। उच्चदाब स्टील उद्योगों की न्यायोचित भलाई का ध्यान वर्तमान समय में हुए पुनरीक्षण में नियामक आयोग द्वारा रखे जाने का उदाहरण भी सामने है। उल्लेखनीय है कि नियामक आयोग द्वारा पुनरीक्षित विद्युत दरों में व्यवसायिक उपभोग हेतु उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली बिजली की दर 5.40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि उच्चदाब स्टील उद्योगों को प्रदाय की जाने वाली बिजली की दर मात्र 4.10 प्रतिशत ही बढ़ी है।

स्टील उत्पादकों ने ऊर्जा प्रभार में बड़ी छूट से बढ़ाया अपना मार्जिन, आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया लाभ

सरकारें जब किसी उद्योग को जब कोई रियायत, छूट या सब्सिडी देती हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन बढे और इसका अंतिम लाभ आम जनता को वह वस्तु सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके लेकिन छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में उल्टी गंगा ही बहाई गई। विगत 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो इस मामले में बड़ी विरोधाभाषी तस्वीर नजर आती है। स्टील उत्पादकों ने उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन दाम कम होने की बजाय बढ़ते चले गये। वर्ष 2018-19 में जहां 100 मिलियन टन उत्पादन पूरे देश में हुआ था और दर 33,833 रु. प्रति टन थी जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 53,036 रु. प्रति टन हो गई। यह दिलचस्प कहानी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेष तौर पर मौजूद है क्योंकि इसमें स्टील उद्योगपतियों के खाते में लाभ का मार्जिन बढ़ाने में मुख्य भूमिका तत्कालीन राज्य सरकार ने निभाई है। छत्तीसगढ़ राज्य इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि देश के कुल स्टील उत्पादन का 30 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में ही होता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानें है। आम जनता को यह अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले।

उद्योगों की बिजली महंगी करना सरकार का मूर्खतापूर्ण निर्णयः भूपेश

नौकरियां दे नहीं रही सरकार, लाखों के रोजगार पर तलवार लटका दी

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोहा उद्योग बंद करने के व्यापारी के निर्णय को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा है कि लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार का मूर्खतापूर्ण निर्णय है. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को ग़लतफ़हमी हो गई है तो वे बिजली का बिल देख लें वे समझ जाएंगे कि दरअसल ग़लतफ़हमी सरकार को हुई है.

छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्पॉन्ज आयरन मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद श्री बघेल ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है कि बिजली के दरों में सिर्फ 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि दरअसल 'लोड फैक्टर इंसेन्टिव' सहित कुछ और छूट बंद करने से उद्योगों को प्रति यूनिट 6.10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली 7.62 पैसे प्रति यूनिट की पड़ रही है. छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से पहली बार उद्योगपति तालाबंदी जैसा बड़ा निर्णय लेने को बाध्य हुए हैं तो इसकी वजह तो होगी ही, ग़लतफ़हमी में इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता.

उन्होंने कहा है कि उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है. तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है. उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि ओडीशा में उद्योगों को बिजली 5 रुपए और पश्चिम बंगाल में 4.91 रुपए की दर से बिजली मिल रही है, यहां तक कि जिंदल पार्क में बिजली 5 रुपए के दर से मिल रही है. तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों इसी दर पर बिजली नहीं देती?. श्री बघेल ने कहा है कि यदि इतनी महंगी बिजली मिलेगी तो छत्तीसगढ़ के उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और इससे राज्य और केंद्र सरकार को ही नुकसान होगा. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ओर से सरकार ने नौकरियों में भर्ती रोक रखी है दूसरी ओर वह कम से कम दो लाख लोगों का रोजगार छीन रही है. अप्रत्यक्ष रूप से इससे दो लाख से बहुत अधिक संख्या में लोगों का रोजगार प्रभावित होगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने, बात पत्र जारी करने तक आई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद पीएम आवास राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. इस मुद्दे पर चर्चा मौजूदा मानसून सत्र में खूब हुई, सड़क पर भी कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया है. यही नहीं पीएम आवास पर सियासी वार और पलटवार अब दिल्ली से भी होने लगा है. दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद से प्रदेश में इस पर सियासत और तेज हो गई है. रोज मीडिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इस बयान आ रहे हैं. चौहान, साय, साव और बघेल जैसे नेताओं ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया है. और बात सरकारी पत्र जारी करने तक आ गई है.

कांग्रेस सरकार ने किया था अन्याय- शिवराज सिंह चौहान

दरअसल बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की थी. उन्होंने प्रदेश में रुके हुए पीएम आवास को जल्द स्वीकृत करने की मांग की थी. केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया. केंद्र सरकार यहां से पैसा भेजती थी लेकिन राज्य सरकार को जितना अंश उसमें डालना था वह पैसा राज्य सरकार ने दिया ही नहीं, जिसके कारण पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने ही नहीं. पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर मदद देने को तैयार है.

कांग्रेस सरकार नहीं दिया था राज्यांश- विष्णुदेव साय

वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया. हमनें अपनी बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के सामने रखी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसे को केंद्र से आवंटित करने की बात की.

गरीबों पर नमक- अरुण साव

वहीं मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के जले पर नमक छिड़कने का काम करती है. कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को पीएम आवास के लिए तड़पाया है. भाजपा की सरकार बनने के बाद 5 हजार आवास शहरों में बनने शुरू हो गए हैं. सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र की ओर से राज्यांश उपलब्ध ही नहीं कराया था. और तो और तत्कालीन पंचायत मंत्री टीए सिंहदेव को पंचायत विभाग से इस्तीफा देना पड़ा था.

चाहे तो पत्र जारी करे दें- भूपेश

इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पीएम आवास को लेकर मेरे खिलाफ झूठे बयान केंद्रीय मंत्री से दिलवाए गए. जिससे कि मुझे झूठा साबित किया जा सके. जबकि सच्चाई ये है कि हमारी सरकार के समय हमने पीएम आवास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया था. केंद्र की ओर से लाभांश नहीं दिया गया. यही नहीं वर्तमान जितनी भी बात आवास को लेकर उसमें साय सरकार बता दें कि एक भी आवास स्वीकृत हुई है या नहीं.

सदन में तो मैंने इस पर प्रश्न किया था, जवाब तो आया नहीं. अब सदन के बाहर कुछ और बात कह रहे हैं. 18 लाख साय सरकार ने बनाने की बात कही है. होर्डिंग में दिख भी रहा है, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है. सरकार सिर्फ कागजों पर चल रही है. और वैसे भी पीएम आवास पर हमारी सरकार में क्या हुआ या क्या नहीं सारा रिकार्ड सरकार के पास है. चाहे तो राज्य और केंद्र सरकार के जो-जो पत्र वो जारी कर दें.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस राज में छग ने ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का निर्माण किया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा नेता झूठ प्रसारित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है, कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में गुजरात से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ में 963936 आवास पूर्ण हो चुके है। जबकि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में मात्र 511547 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड से शीर्ष पर है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 1176142 आवास आवंटित किया था, जिसमें से 963936 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 2,12,206 ग्रामीण आवास निर्माणाधीन है। वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 3 लाख 9 हजार आवास का आवंटन किया था, जिसमें से 279000 से अधिक आवास पूर्ण बन चुके हैं, उन्हें हितग्राहियों को दे दिया गया है और शेष आवास निर्माणधीन है। छत्तीसगढ़ को आवंटित प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहर आवास योजना की राज्यांश की राशि राज्य सरकार ने पूरा दे दिया था। 2011 के आर्थिक जनगणना के अनुसार 18 लाख आवास मिलना था,

विधानसभा घेराव के बाद भी कानून व्यवस्था बदहाल-कांग्रेस

रायपुर। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में हत्या और चाकूबाजी, लूट, डकैती की घटनाएं रुक नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूटी है। प्रदेश में रोज आपराधिक घटनायें बढ़ते जा रही है। बलात्कार, लूट, चाकूबाजी, चैनस्नेचिंग, गुंडागर्दी की खबरों से अखबार भरा पत्र है। गैंगवार हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलिया चल रही है। भाजपाई दृष्टिदोष का शिकार हो गये है। उन्हें आम आदमी की परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। सत्ता के मद में भाजपाई जनसरोकारों को भूल बैठे है। राजधानी में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या लूट चाकूबाजी की घटना नहीं होती है। रायपुर तो चाकूपुर बन गया है। कल ही एक युवक को बदमाशों ने मरणासन्न होते तक पीटा, वहीं एक अन्य युवक की हत्या कर दी गयी। प्रदेश का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां रोज खूनी वारदात नहीं होती हो। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 7 महीने की साय सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल हो गई है, 7 माह में ही राजधानी में गोलीबारी की 4 घटना हुई है। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर राज्य मे पैर पसार रहे है

बृजमोहन संघ से पूछे एससी, एसटी को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाते?

रायपुर। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से यह पूछने की किसी एससी, एसटी, ओबीसी को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बृजमोहन सहित पूरी भाजपा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा संसद में उठाये जा रहे जनहित के मुद्दो से तिलमिला जाती है। राहुल गांधी संसद में देश के मजदूरों, किसानों, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला ओबीसी की आवाज बुलंद कर रहे है तो भाजपा को पीड़ा हो रही है। बौखलाहट में भाजपा के सांसद अनर्गल बयानबाजी करने लगते है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को एससी, एसटी, ओबीसी की इतनी ही चिंता है तो वे बताये के भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस में आज तक किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया? संघ में जितने भी प्रमुख बनाये गये वे सारे के सारे रज्जू भैया को छोड़कर सभी एक ही समुदाय से क्यो थे? संघ में दूसरे समाज के लोगों को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाया जाता बृजमोहन इसका जवाब देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बृजमोहन 35 सालों से रायपुर शहर दक्षिण से विधायक चुने जाते रहे है।

जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। नवागढ़ के जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने बेमेतरा कलेक्टर के दिए आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है। दरअसल, अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व अन्य ने कुछ आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया। इसमें प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई, जिसमें लगे हुए आरोपों का उल्लेख किया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई।

प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर हाईकोर्ट की सख्ती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत और सिटी बसों की अनियमितता पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव और कमिश्नर से व्यक्तिगत शपथ पत्र पर जवाब मांगा है कि आम लोगों के लिए इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ई-बसें कब तक चालू होंगी. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 9 शहरों में चल रही 378 बसों में से अब केवल 272 बसें ही रह गई हैं, जिसमें से 106 बसें काम नहीं कर रही हैं और इनमें से सिर्फ 70 से 80 बसें ही सड़क पर चल रही हैं. शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सिटी बसें केवल नगरीय निकाय क्षेत्र में ही चलती हैं. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल ने शासन से पूछा कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की हालत कब सुधरेगी. उन्होंने कहा कि गाय सड़कों पर चल रही है, प्रदेश में जो बसें अन्य शहरों के लिए चलती हैं उनकी भी हालत खराब है. कोर्ट ने शासन से कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य में बसों की संख्या बहुत कम है. जो बसें चल रही हैं उनमें भी लूटपाट और यात्रियों की सुरक्षा की समस्याएं हैं. कोर्ट ने शासन को न केवल सिटी बस सेवा को सुधारने का निर्देश दिया.

292 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त, भारत सरकार ने दिया प्रमाणपत्र

टीबी मुक्त अभियान में तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़

महासमुंद. टीबी मुक्त भारत

TB MUKT PANCHAYAT
Panchayati Raj
TB MUKT PANCHAYAT 2023
This is to certify that GRAM PANCHAYAT - PACHRI
located in Mahasamund of Mahasamund in the State of Chhattishgarh has been declared TB Free for the year 2023
Congratulations to the residents for your significant achievement and wishing you success in sustaining TB free status in the coming years.
Date 11 March 2024
TB Harega, Desh Jeetega!
Shri. Prabhat Malik (I.A.S.)
Collector
Mahasamund C.G.

के लिए चलाया जा रहा अभियान अब धरातल पर दिखने लगा है. इस अभियान के परिणामस्वरूप महासमुंद जिले की 292 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है. इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने जहां पंचायतों को 'टीबी मुक्त पंचायत' का प्रमाण पत्र दिया है, वहीं स्वास्थ्य अमला सहित ग्रामीण भी इस उपलब्धि से खुश हैं. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले को 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य था. यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित समय सीमा 2030 से पांच वर्ष पहले हासिल करने का है. जिले में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच जिले के 551 पंचायतों मे से 292 पंचायतों का चयन कर संभावित ग्राम पंचायतों में प्रति हजार जनसंख्या पर 30 लोगों की जांच की गई. टीबी उन्मूलन के इस अभियान में जिले की स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर मेहनत की है.

नियमित जांच, समय पर उपचार और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से टीबी के मामलों की पहचान और उपचार किया गया, जिसका परिणाम रहा कि जिले के 292 ग्राम पंचायते अब टीबी मुक्त हो गई है. इस सफलता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का डॉ. पी कुदेशिया का कहना है कि यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और इस वर्ष के अंत तक जिले की सौ फीसदी पंचायते टीबी मुक्त हो जाएगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 को वाराणसी में आयोजित विश्व टीबी दिवस कार्यक्रम में टीबी मुक्त पंचायत की पहल की थी. इसके अंतर्गत महासमुंद जिले के इन 292 ग्राम पंचायतों ने मान्य संकेतकों का मापन एवं सत्यापन कर टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त किया है. भारत में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे नंबर पर है और छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला टीबी मुक्त अभियान में प्रथम स्थान पर है.

रिटायर्ड पॉवर इंजीनियर्स-ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा स्टील उद्योगों द्वारा बिजली दरों में छूट लेने का प्रयास अनुचित

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य रिटायर्ड पॉवर इंजीनियर्स-ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर राज्य के स्टील उद्योगों द्वारा बिजली की दरों में छूट लेने के प्रयास को अनुचित बताया है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि स्टील उद्योग नई बिजली दरों को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आम उपभोक्ताओं के घरेलू तथा किसानों के बिजली बिल की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं दूसरी तरफ उच्च दाब उपभोक्ताओं स्टील इंडस्ट्रीज में मात्र 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। स्टील इंडस्ट्रीज को पिछले कई वर्षों से मिल रहे अवांछित 25 प्रतिशत लोड फैक्टर की छूट को युक्तिसंगत करते हुए दस प्रतिशत किया गया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उद्योगों का यह कहना कि बिजली की दरें 25 प्रतिशत बढ़ गई है, सत्य से परे और गुमराह करने वाली है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा दर में मात्र चार प्रतिशत (मात्र 25 पैसे प्रति यूनिट) की वृद्धि की गई है। लोड फैक्टर की अवांछित और अनुचित छूट को 25 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया गया है। स्टील उद्योगों को फायदा देते हुए ऑफ पिक अवर्स के समय को छह घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे का किया गया है। इससे उद्योगों को छह घंटे के बजाय अब आठ घंटे सामान्य दरों की तुलना में 80 प्रतिशत दर पर बिजली मिलेगी। इस तरह स्टील इंडस्ट्रीज की विद्युत दरों को अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि प्रतिवर्ष जुलाई से लेकर नवम्बर माह तक लोहे की मांग कम होने के कारण इसके मूल्य में गिरावट आती है

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.